वर्ष : 17 ❖ अंक : 247 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक
शनिवार, 15 अप्रैल 2023

हर किसी को देशद्रोही कहना खतरनाक चलन : खड़गे 3

एनएसए जैसे दमनकारी 'काले कानूनों' को रद्द करें : सुखबीर बादल 8

सीएम गोले की विपक्षी दलों को चुनौती, कहा- साबित करें कि 371एफ का हुआ है उल्लंघन

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 14 अप्रैल । मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने विपक्ष पर धारा 371एफ समाप्त होने के नाम पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

राजधानी में आयोजित अम्बेडकर जयंती को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष यह कहकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि संविधान की धारा 371एफ को उड़ा दिया गया है। सिक्किम के लोगों को इन नकली राजनेताओं से सावधान रहना चाहिए। 371 एफ को देश का सर्वोच्च न्यायालय भी निरस्त नहीं कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री और वित्त मंत्री भी इस मसले पर अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही कहा कि अगर सच में सिक्किम से 371एफ को समाप्त कर दिया गया है तो पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग तिनकिताम में भाइचुंग भूटिया की जमीन अपने नाम पर करवा लें। अगर वे ऐसा करवा लेते हैं तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं। क्योंकि 371 एफ सिक्किम में भूटिया-लेप्चा समुदाय की भूमि की पूरी तरह से रक्षा करता है, सिक्किम में अन्य समुदाय उनकी भूमि नहीं खरीद सकता है।

मुख्यमंत्री गोले ने कहा, आईपीआर विभाग द्वारा जारी विज्ञापन के तहत सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में अतिरिक्त निदेशक के रिक्त पदों के लिए एसपीएससी (सिक्किम लोक सेवा आयोग) ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। अगर कोई आरसी धारक इसके लिए आवेदन जमा करता है और एसपीएससी द्वारा आवेदन स्वीकार किया जाता है तो मैं इसके दूसरे दिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और मेरे कैबिनेट सहयोगी भी इसके लिए खुले तौर पर तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि चूंकि वह और उनका परिवार सिक्किम के मूल निवासी हैं, इसलिए 371एफ की पूरी तरह से रक्षा करना उनका पहला कर्तव्य है। इसी तरह सिक्किम विधानसभा में पारित प्रस्ताव के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार 371 एफ को कभी समाप्त नहीं करेगी। देश की संसद में हाल ही में पारित एक बिल केवल आयकर से संबंधित है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने उन्हें सूचित किया है कि इससे सिक्किम के मूल निवासियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां के लोगों के विरोध के कारण ही राज्य

सरकार को 10 अप्रैल को सिक्किम विधानसभा में एक प्रस्ताव लाना पड़ा।

सीएम गोले ने इसके साथ ही कहा कि हम अपने अधिकारों की बात करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों की कभी बात नहीं करते। हममें से कोई भी यह नहीं सोचता कि हम अपने समाज, राज्य और देश को क्या मदद कर सकते हैं और क्या दे सकते हैं। हम केवल लेना चाहते हैं देना नहीं।

डॉ. बीआर अम्बेडकर की जयंती मनी

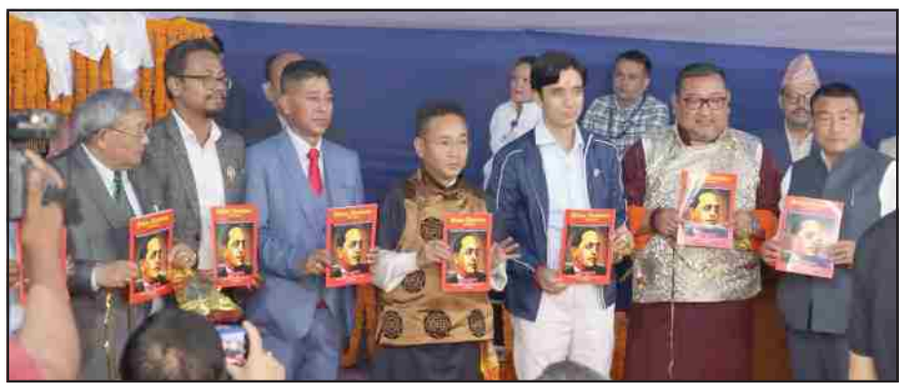

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 14 अप्रैल । सिक्किम विधानसभा परिसर में आज संविधान निर्माता डॉ बीआर अम्बेडकर की 132वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष अरुण उप्रेती, उपाध्यक्ष सांगे लेप्चा, राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद इंद्र हांग सुब्बा, सीएम के राजनीतिक सचिव जैकब खालिंग के अलावा अन्य अधिकारी एवं गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री गोले ने राज्य में अनुच्छेद 371एफ के कमजोर होने के मामले में अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 371एफ के तहत राज्य को दिए गए और भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित अधिकारों के साथ कभी छेड़छाड़ या उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

वहीं अपने वक्तव्य की शुरुआत में नेपाली नव वर्ष के अवसर पर सभी को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने राष्ट्र के प्रति डॉ अम्बेडकर के समर्पण एवं योगदान को याद किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज में असमानता दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को डॉ अम्बेडकर के अनुकरणीय योगदान को स्वीकार करते हुए एक समान समाज बनाने हेतु उनकी विचारधारा को आत्मसात करना चाहिए। वहीं कार्य संस्कृति के महत्व के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को स्वार्थ पर ध्यान न देते हुए राज्य के लाभ हेतु कुशलतापूर्वक अपनी पेशेवर सेवा देने की आवश्यकता है।

इससे पहले, कार्यक्रम की शुरुआत में ऑल सिक्किम शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री गोले को सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और एससी समुदाय की 'भीम चेतना' नामक एक पत्रिका का विमोचन भी किया। इसके अलावा उन्होंने अनुसूचित जाति समुदाय के स्कूल में अव्वल आने वाले एवं अन्य उपलब्धियां हासिल करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित भी किया।

इसके अलावा ऑल सिक्किम शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बिकाश सुनाम ने राज्य में हर प्रकार का विकास सुनिश्चित करने हेतु निरंतर समर्थन और सहयोग प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।

जनता से सच छिपाने की कोशिश कर रहे हैं सीएम : भाइचुंग भूटिया

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 14 अप्रैल । केंद्रीय वित्त विधेयक के माध्यम से सिक्किमी परिभाषा के कमजोर होने के मामले में हाम्रो सिक्किम पार्टी ने एक बार फिर एसकेएम अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) पर हमला बोला है। इसके अंतर्गत एसएचपी अध्यक्ष भाइचुंग भूटिया ने मुख्यमंत्री गोले को स्पिन मास्टर बताते हुए कहा है कि वे सीधे सही बात न बताते हुए उसे गोल-गोल घुमा कर जनता से सच छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही भूटिया ने सीएम गोले से कई सवाल भी पूछे हैं।

भूटिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद कि 10 अप्रैल को विधानसभा के प्रस्ताव में सिक्किमी परिभाषा को कमजोर कर दिया गया है, मुख्यमंत्री फिर से सार्वजनिक रूप से कुछ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोले को दिल्ली में भाजपा के अपने नीति निर्माताओं के साथ सिक्किमी परिभाषा के कमजोर किए जाने के बाद किए गए मेरे सभी पत्रकार सम्मेलन और बयानों को देखना चाहिए। उससे वह समझेंगे कि जो लोग आयकर छूट का लाभ लेने के लिए सिक्किम आएंगे, 10-15 साल बाद वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और अनुच्छेद 14 के तहत जमीन खरीदने सहित नौकरियों और अन्य अधिकारों के लिए छूट मांगने के आधार के साथ यह कैसे करेंगे।

भूटिया के अनुसार सिक्किमी परिभाषा के कमजोर पड़ने के इस प्रकरण ने राज्य में भानुमती का पिटारा खोल दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री गोले से सवाल करते हुए कहा कि यदि सिक्किमी परिभाषा कमजोर नहीं हुई है, तो मंत्री केएन लेप्चा ने सदन में यह क्यों कहा कि सिक्किम सरकार के कानून 1974 में वर्णित सिक्किमी परिभाषा में वित्त विधेयक के दो नये उप खंडों (4) एवं (5) के अंतर्गत आने वाले लोग सिक्किमी परिभाषा में शामिल नहीं होते हैं? इसके अलावा सिक्किम सरकार ने एक बयान क्यों जारी किया कि हाल ही में आयकर धारा 10 (26एएए) में संशोधन करते हुए वित्त विधेयक, 2023 (संख्या 8) को पारित करने से आम सिक्किमवासियों की भावनाएं आहत हुईं हैं और वे सिक्किमी परिभाषा को लेकर संशय की स्थिति में हैं? इसके साथ ही राज्य सरकार ने क्यों कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26एएए) के तहत दो नए उपखंड (4) एवं (5) को जोड़ने से सिक्किम की तीन मूल जातियां अन्य के साथ मिला दी गईं हैं? उन्होंने यह भी सवाल किया कि यदि वित्त विधेयक 2023 से सिक्किमी परिभाषा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो राज्य सरकार इसमें संशोधन हेतु केंद्र की भाजपा सरकार से भीख क्यों मांग रही है?

इसके अलावा भूटिया ने एसकेएम सरकार पर राज्य में हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम गोले एक तरफ सिक्किम की शांति और सद्भाव के बारे में बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर एसकेएम के गुंडे हमला करने और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हाल ही में सिंगताम में एसकेएम के गुंडों द्वारा केशव सापकोटा नामक एक पूर्व सैनिक पर किया गया हमला इसका ताजा उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि सिक्किम कभी भारत का सबसे शांतिपूर्ण राज्य हुआ करता (शेष पृष्ठ ०३ पर)

अम्बेडकर के सपने से देश अभी कोसों दूर : चामलिंग

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 14 अप्रैल । सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा (एसडीएफ) प्रमुख पवन चामलिंग ने आज अम्बेडकर जयंती पर कहा कि एक प्रखर राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक एवं भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब ने जिस भारत की कल्पना की थी, वह आज भी दूर की कौड़ी है। आज भी समाज में असमानता, भेदभाव और पिछड़ी जातियों के प्रति अत्याचार देखने को मिलता है, जो दुर्भाग्यजनक है। ऐसे में देश में हम हर वर्ष उस व्यक्ति की जयंती मनाते हैं जो पूरी जिंदगी अनुसूचित जातियों एवं दलितों के अधिकारों के लिए लड़ा। हालांकि सिक्किम में उन्होंने ऐसे मामलों में कमी की बात कही।

चामलिंग ने कहा, डॉ अम्बेडकर ने देश में समानता लाने हेतु जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने दलितों और अनुसूचित जातियों के उत्थान के साथ ही जाति व्यवस्था के सुधार की वकालत की। हालांकि अनुसूचित जाति और दलितों की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु संस्थागत रूप से कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन डा अम्बेडकर ने जिस तरह के भारत की कल्पना की और उसके लिए संघर्ष किया वह अभी भी एक दूर का सपना है। आज भी विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और दलितों के प्रतिनिधित्व की समान कमी देखी जा सकती है। उन्होंने बताया, 17वीं लोकसभा में सवर्ण जाति के 232, ओबीसी के 120 और अनुसूचित जातियों के 86 सांसद हैं। वहीं न्यायपालिका में भी अनुसूचित जाति और दलितों का न्यूनतम प्रतिनिधित्व है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नौ जजों के नाम प्रस्तावित किए, जिससे जजों की कुल संख्या 33 हो गई। लेकिन इनमें से केवल एक जज ही अनुसूचित जाति से थे।

उन्होंने आगे कहा कि आज भी देश में दलितों के खिलाफ हिंसा व्यापक रूप से है। 2022 में इंद्र मेघवाल नामक एक नौ साल के दलित लड़के की उसके एक शिक्षक ने केवल इसलिए पिटाई की क्योंकि उसने ऊंची जातियों के लिए बने पानी के बर्तन को छू लिया था। ऐसी

घटनाएं काफी दुर्भाग्यजनक हैं और यह वही भारत है जिसमें हम आज रहते हैं।

वहीं इस संदर्भ में सिक्किम का स्थिति का जिक्र करते हुए चामलिंग ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति और दलितों के खिलाफ भेदभाव के प्रति संवेदनशील होने के नाते हमने इस तरह के अत्याचारों से बचाव हेतु विभिन्न कानून बनाए हैं। उनके अनुसार, सिक्किम में ऐसे जघन्य जातिगत अपराध के मामले कम ही होते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान (शेष पृष्ठ ०३ पर)

राज्यपाल ने की 'गवनर्स बीआर अम्बेडकर प्रतिभा कप' की घोषणा

विजेता छात्र व टीम को मिलेगा एक लाख रुपये का पुरस्कार

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 14 अप्रैल । बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं संस्कृति विभाग, उप्र के संयुक्त तत्वावधान में बाबासाहेब राष्ट्रीय संगोष्ठी पर आज बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में भव्य समारोह का आयोजन किया गया जिसमें सिक्किम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। संगोष्ठी का विषय 'अंबेडकर के वैज्ञानिक स्वभाव और राष्ट्र निर्माण के अप्रकाशित पहलू' था।

कार्यक्रम के आरंभ में परंपरागत दीप प्रज्वलन के साथ कुलगीत गाया गया। कार्यक्रम में बाबा साहब अंबेडकर की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी भी रखी गई थी। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे क्विज, वाद विवाद, रंगोली

आदि रखा गया। कार्यक्रम में बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं संस्कृति विभाग, उप्र की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया जो सभी के दिलों को जीतने में सफल रहा।

कार्यक्रम के अन्तर्गत में विभिन्न वक्ताओं ने बाबा साहब अंबेडकर के अनछुए पहलुओं पर अपने मत प्रस्तुत किए। सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने उक्त संगोष्ठी में सम्मिलित होना हर्ष एवं गर्व का विषय बताया। बाबा अंबेडकर को बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी बताते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने समाज में स्थापित बुराइयों के प्रति लोगों को जागृत करने का काम किया और एक मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत वर्ष की पहचान बनाई।

बाबा अंबेडकर के अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने कहा कि बाबा साहब किसी लोकतंत्र के पुष्पित पल्लवित होने के लिए केवल मताधिकार को ही नहीं बल्कि उसके साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय भी देना समझते थे। उनके सामाजिक लोकतंत्र का मतलब समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व हैं और मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए मूल्य स्तंभ है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के पूरे (शेष पृष्ठ ०३ पर)

राज्यस्तरीय बैशाखी समारोह शुरु

अनुगामिनी नि.सं.

नामची, 14 अप्रैल । विक्रम संवत 2080, बैशाखी पर्व के उपलक्ष्य पर आज नामची सांस्कृतिक मंच द्वारा स्थानीय किसान मार्केट में आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय समारोह भव्य समारोह के बीच शुरू हुआ। इस अवसर पर राज्य के भवन व आवास मंत्री संजीत खरेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके अलावा समारोह में नामची नगर परिषद अध्यक्ष गणेश राई, जिला अध्यक्ष सुश्री अंजिता राई, भवन व आवास विभागीय चेयरमैन ताशी दोर्जी तामंग के साथ ही अन्य लोग मौजूद थे। उत्सव की शुरुआत सेंट्रल पार्क से निकाली गई एक शोभायात्रा से हुई जो कम्युनिटी हॉल होते हुए किसान मार्केट में सम्पन्न हुई।

इस अवसर पर अपने वक्तव्य में मुख्य अतिथि संजीत खरेल ने नए साल की शुभकामनाएं देते हुए

पहली बार राज्य स्तरीय बैशाखी पर्व के आयोजन हेतु मंच की सराहना की। इसके अलावा, उन्होंने इस उत्सव के महत्व के साथ-साथ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा भाषाई विविधता को संरक्षित और प्रचारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही उन्होंने राज्य के सभी समुदायों की कला, संस्कृति और भाषाओं के प्रचार एवं संरक्षण की दिशा में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग के नेतृत्व में राज्य सरकार के समर्थन पर प्रकाश डाला।

इस दौरान आयोजन समिति की ओर से समाज कल्याण में योगदान हेतु मंत्री खरेल को प्रशंसा पत्र भी भेंट किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगारंग पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य एवं गीत प्रस्तुत किए गए। साथ ही छात्रों ने बैशाखी पर्व पर निबंधों का पाठ भी किया।

राज्यपाल आयार्च ने यूपी की राज्यपाल से की मुलाकात

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 14 अप्रैल । सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राजभवन, लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल से मुलाकात की। दोनों राज्यपालों ने अपने-अपने राज्यों के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक के दौरान सिक्किम के राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को राज्य में पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों से अवगत कराया। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल

ने कृषि, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन में राज्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

दोनों राज्यपालों ने दोनों राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के तरीकों पर भी चर्चा की और उन्होंने अपने राज्यों और देश के हितों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

बिहू उत्सव में रथ पर सवार होकर पहुंचे पीएम मोदी, कहा– असम बन रहा 'ए वन' राज्य

गुवाहाटी, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को असम की राजधानी गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन किया। उन्होंने पूर्वोत्तर के पहले एम्स को देश को समर्पित किया। इसके अलावा उन्होंने तीन अन्य मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। इसमें गुवाहाटी स्थित कोकराझार, नलवारी और नगांव महाविद्यालय और चिकित्सालय शामिल हैं। एम्स गुवाहाटी की आधारशिला मई 2017 में पीएम मोदी ने ही रखी थी। इसे 1120 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा पीएम ने असम को 14300 करोड़ रुपये की सौगात दी।

इस दौरान पीएम ने कहा कि आज उत्तर पूर्व को अपना पहला एम्स और असम को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। आईआईटी-गुवाहाटी के साथ मिलकर आधुनिक रिसर्च के लिए 500 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी वाले अस्पताल का भी शिलान्यास हुआ है। असम के लाखों-लाख साथियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम मिशन मोड पर शुरू हुआ है। आईआईटी-गुवाहाटी के साथ मिलकर आधुनिक रिसर्च के लिए 500 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी वाले अस्पताल का भी शिलान्यास हुआ है। असम के लाखों-लाख साथियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम मिशन मोड पर शुरू हुआ है। पिछले नौ साल में हमने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और इसलिए हर कोई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करता है। प्रधानमंत्री ने कहा, हम आपके सेवक होने की भावना से काम करते हैं, इसलिए नॉर्थ-ईस्ट हमें दूर भी नहीं लगता और अपनेपन का भाव भी बना रहता है। आज नॉर्थ-ईस्ट में लोगों ने विकास की बागडोर आगे बढ़कर खुद संभाल ली है। भारत के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आज कल नई बिमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं और 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो उससे कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है। वह शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया, उन्हें श्रेय क्यों नहीं मिलता। श्रेय के भूखे लोगों और जनता की राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है।

पीएम ने कहा कि हमने बीते वर्षों में 15 नए एम्स पर काम शुरू किया। इनमें से अधिकतर में इलाज और पढ़ाई दोनों सुविधा शुरू हो चुकी है। एम्स गुवाहाटी भी इसका परिणाम है कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है। यह असम की जनता का प्यार है कि मुझे खींचकर ले आता है।

उन्होंने कहा कि की सरकारों में नीति, नीयत और निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि 'राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम' इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती हैं। इसलिए हमने वोटबैंक की बजाए देश की मुश्किलों को कम करने पर ध्यान दिया। हमने लक्ष्य बनाया कि हमारी बहनों को इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। हमने तय किया कि किसी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज न टालना पड़े। हमने प्रयास किया कि हमारे गरीब परिवारों को भी घर के पास ही बेहतर इलाज मिले।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह करीब 11.30 बजे गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), गुवाहाटी और तीन अन्य मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। उन्होंने आपके द्वार आयुष्मान अभियान की शुरुआत भी की। इस अवसर पर वे गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में बिहू नृत्य के विश्व रिकॉर्ड के भी साक्षी बनेंगे, जहां एक साथ 11 हजार से अधिक कलाकार एक साथ बिहू नृत्य करेंगे।

प्रधानमंत्री ने असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट, पलाशबाड़ी और सुआलकुची को जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल और शिवसागर के रंग घर के सौंदर्यीकरण कार्य की आधारशिला रखी। एम्स का निर्माण केंद्र द्वारा 1,123 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है और इसमें 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल और 100 एमबीबीएस सीटें होंगी। पीएम मोदी ने एम्स परिसर से राज्य सरकार द्वारा निर्मित नलबाड़ी (615 करोड़ रुपये), नागांव (560 करोड़ रुपये) और कोकराझार (535 करोड़ रुपये) में तीन मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल उद्घाटन भी किया।

प्रधानमंत्री ने आईआईटी गुवाहाटी परिसर के भीतर एक शोध अस्पताल की आधारशिला भी रखी, जिसे आईआईटी गुवाहाटी और असम सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा, जो शुरुआत में 600 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। पीएम मोदी ने 1.1 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए, जिन्हें हर साल पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रूप से तीन परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इनमें असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड (एपीएल) द्वारा डिब्रूगढ़ के नामरूप में 500 टन प्रति दिन (टीपीडी) क्षमता वाला एक मेथनॉल संयंत्र है, जिसका निर्माण 1,709 करोड़ रुपए के निवेश से किया गया है। पीएम ने एक और बड़ी परियोजना लॉन्च की, वह ब्रह्मपुत्र पर पलासबाड़ी-सुआलकुची पुल है। प्रधानमंत्री ने राज्य में पुलिस अधिकारियों के लिए 'असम कॉप' मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे याद है कि जब मैं विधानसभा चुनाव के दौरान यहां आया था, तो मैंने कहा था कि वह दिन दूर नहीं है जब लोग 'ए फॉर असम' कहेंगे। आज, असम वास्तव में एक ए वन राज्य बन रहा है। आज असम और पूर्वोत्तर को एम्स गुवाहाटी और तीन नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी गई है। आज पूर्वोत्तर की रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी कई परियोजनाएं भी शुरू की गईं।

उन्होंने कहा, यह समारोह 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का प्रतिबिंब है। यह उत्सव 'सबका प्रयास' के साथ एक विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए एक प्रेरणा है। इसी भावना के साथ पूर्वोत्तर और असम के विकास के लिए आज कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है और कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है।

महाराष्ट्र आने से पहले माफी मांगे राहुल गांधी : बावनकुले

मुंबई, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले हिंदुत्व विचारक वी डी सावरकर के खिलाफ की गई अपनी सभी टिप्पणियों को वापस लेना चाहिए। बावनकुले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए राहुल गांधी के मुंबई आने की संभावना के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के बैनर तले उद्धव ठाकरे की शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस की पहले महाराष्ट्र में सरकार थी। हालांकि, पिछले साल शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में इस सरकार को गिरा दिया गया था। शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया था। भाजपा ने गांधी पर सावरकर का बार-बार 'अपमान' करने का आरोप लगाया है।

बावनकुले ने कहा, अगर राहुल गांधी मातोश्री (ठाकरे के मुंबई स्थित घर) जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने बार-बार और जानबूझकर सावरकर पर निशाना साधा है। इसलिए, महाराष्ट्र आने से पहले उन्हें पहले माफी मांगनी चाहिए और सावरकर के खिलाफ अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने विपक्षी एकता को मजबूत करने के अपनी पार्टी के प्रयासों के तहत हाल ही में राकांपा प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी, जिसके बाद ठाकरे के साथ उनकी संभावित बैठक की चर्चा शुरू हो गई है।

ठाकरे ने पिछले महीने मालेगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि वह सावरकर को अपना 'आदर्श' मानते हैं और कांग्रेस नेता को उनका 'अपमान' करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा था कि एमवीए का गठन लोकतंत्र की रक्षा के लिए किया गया था और इसके लिए एकजुट होकर काम करना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा था कि गांधी द्वारा उकसाने के लिए जानबूझकर प्रयास किए जा रहे हैं। गांधी ने पिछले महीने विभिन्न मुद्दों पर भाजपा द्वारा बार-बार की माफी की मांग के बारे में पूछे जाने पर कहा था, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगते हैं।

GOVERNMENT OF SIKKIM,
ROADS AND BRIDGES DEPARTMENT,
DISTRICT SORENG.

NIT No.: 150/ GOS/DIVN/R&B/SRG/DST/537 Date: 10 / 04 /2023

NOTICE INVITING TENDER

For and on behalf of the Governor of Sikkim, Divisional Engineer (Soreng), Roads and Bridges Department invites sealed tenders under single bid system from the eligible contractors of Class III Grade, enlisted with the Sikkim Public Works Department through competitive bidding within the territorial jurisdiction of the 11-Gelling Baigunay GPU where the works are to be executed, for the execution of the work with the details as under :-

Sl. No.	Name of work	Bid security 2.5% of the bid value	Bid value	Cost of tender/ bid form)	Completion period
1.	Construction of road from ICDS turning to Lower Bhimsing Gaon under Soreng Sub Division in Soreng District, Sikkim Km 1.75.	₹ 3.52 Lakh	₹ 141.03 Lakh	₹ 0.30 Lakh	12 Months

Note: The Earnest Money Deposit indicated in the above table is exempted for all Enlisted Women Contractors participating in the bidding process. In case of such bidder being accepted as L1 bidder, the issue of the Work Order shall be governed by Notification No:104/R&B Dated 08/10/2020.

Sl. No.	Particulars	Date & Time
1	Date of submission of application along with Bank receipt	25/04/2023 up to 1600 hrs.
2	Date of issue of Tender Documents and Tender Form	26/04/2023 up to 1600 hrs.
3	Submission of bid documents	27/04/2023 up to 1200 hrs.
4	Opening of bid documents	27/04/2023 at 1300 hrs.
5	Place of opening of bids	Office of the Divisional Engineer, Roads and Bridges Department, Government of Sikkim, Soreng.

Divisional Engineer (Soreng),
Roads and Bridges Department,
Government of Sikkim, Soreng.

Divisional Engineer
Roads & Bridges Deptt.
Government of Sikkim
Soreng

CONDITIONS OF CONTRACT:

1. The intending tenders/contractors should apply in writing for issue of tender documents. The application would invariably be signed by the contractor himself/herself. The tender document shall not be issued to any person other than the **INTENDING TENDER**.
2. The Contractor should be an elector of Soreng-Chakung Constituency and residential address in the Enlistment Certificate should be within the territorial jurisdiction of the same constituency.
3. The applicants should enclose attested copies of the following along with the application
   a) Validated/Updated Contractor Enlistment Certificate. Further, it is mandatory to produce the Original Validated/Updated Enlistment Certificate during sale/issue of the Tender Document for verification.
   b) Latest Goods & Service Tax Clearance Certificate issued from the office of the Commercial Tax (To be submitted by the successful bidder only before issuance of Work Order as per Notification No.: 07/GOS/CTD/2018-2019, dated: 27/06/2018
   c) PAN Card
   d) Photo copy of latest voter ID card with both side printed for proof of their territorial constituency.
   e) Bank Receipt in Original
4. The prescribed Non-Transferable Tender Documents can be obtained from the office of the Accounts Officer, Roads and Bridges Department, on production of requisite Bank Receipt of the State of Sikkim (non-refundable) under the receipt head "0059-80-800.01- other receipts", during the time schedule mentioned above.
5. Earnest money deposit @ 2.5% of the cost put to tender shall be deposited in the form of Temporary Deposit Receipt/Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee from State Bank of Sikkim or any nationalized bank in favour of the Accounts Officer, Roads and Bridges Department, Soreng. Tender form shall be issued only on production of the same. In case of the Enlisted Women Contractors participating in the bidding, the cost of the earnest Money Deposit shall be governed by Notification No. 104/R&B Dated 08/10/2020.
6. The soft copy of the BOQ shall be provided along with the tender documents on submission of Earnest Money Deposit as mentioned vide sl. no. 4. The intending bidder shall submit his/her bid in the printed format as per the soft copy of the BOQ provided. In case the bidder submits the bids in hand written format, the same shall be summarily rejected.
7. The tenderer shall inspect the site and have their own and correct assessment before submitting the bid.
8. The Tender Documents, including the Tender Form with quoted offer in the BOQ provided should be placed in a sealed cover with the name of the tenderers and the name of the work superscripted on it. The Tenderer should sign on every page of the tender documents as acceptance of the general direction and conditions of the contract and other laid down norms. Supporting documents listed vide Sl. No. 2 should be enclosed with the offer.
9. Sealed tenders may be deposited in the Tender Box in the office of the Superintending Engineer (Soreng), Roads and Bridges Department, Soreng, on the date and within the time indicated above.
10. The rate quoted should be both in figures and words and should be inclusive of GST and all other Taxes in vogue.
11. Over writing and correction should be avoided and if made should be authenticated. Incomplete/Conditional tenders shall be rejected forthwith.
12. Tenders will be opened by the Tender Opening Committee as prescribed by the Government in the presence of the tenderers on the date and time indicated above.
13. In case of any discrepancy in the specifications printed in the BOQ issued with the tender documents, specifications as per approved Schedule of Rates-2020 will be taken as correct. For items outside the SOR, the decision of the Principal Chief Engineer cum Secretary/Head of the Department will be final.
14. The Department reserves the rights to with hold payments to the contractor unless test certificates are produces by the contractor when called upon to do so.
15. Avoidable damages due to negligence of the contractor shall be at his/her own risk and cost. The Department shall not be liable for payment of such damages (if any), including accidents to labours at site.
16. The offer shall remain valid for a period of 90 days. The work should commence within 15 days from the sate of issue of work order.
17. All the conditions as mentioned in the NIT shall be deemed to be a part of the agreement to be entered with the contractor. Security deposit shall be collected by deductions from the running bills of the contractor @5% of the value of work done.
18. The Department reserves the right to accept any or all tenders without assigning any reason thereof.
19. The recoveries i/c deduction of taxes and duties as applicable shall be as per the rates notified by the Government from time to time and as applicable on the date of payment.
20. Subletting of contract work is against the norms and if it comes to the notice, the original contract shall be cancelled and appropriate action shall be initiated as per the rules.
21. In case of manpower employed by the contractor are from outside the State or neighboring countries, it shall be the responsibility of the contractor to get them registered with the Labour Department, Government of Sikkim as per the relevant Labour Laws.
22. The contractor shall also make arrangements to have photographs of the works taken up at least of three stages during the construction period. i.e. beginning, middle and completion stage.
23. Quarrying of non-stock materials shall be allowed only from designated/approved quarries.
24. The Specifications in execution of the works are to be followed as per the guidelines laid by the Ministry of Roads Transport & Highways (MoRTH).
25. Damage to properties in and around the work site must be avoided at all cost. The contractor shall be held responsible for any act of negligence and shall bear the responsibility to repair/restore such damage.
26. Expenditure involved for material testing like cube strength of concrete, crushing strength of road metals etc., at site or in laboratories shall be borne by the contractor. The contractor shall make necessary arrangements accordingly as and when instructed by the concerned authorities.
27. The cost of stock materials and bridges parts if any supplied from the Departmental store will be deducted from the contractors' bills as per the prevalent recovery rate.
28. Defect liability period for the pavement work shall be for a period of five (05) years which shall not cover the damages due to natural calamities, formation sinking, landslides etc.

Divisional Engineer (Soreng)
Roads and Bridges Department
Government of Sikkim
Soreng

R.O. No.: 15/IPR/PUB/Classi/23-24, DT.: 13.04.2023

हर किसी को देशद्रोही कहना खतरनाक चलन : खड़गे

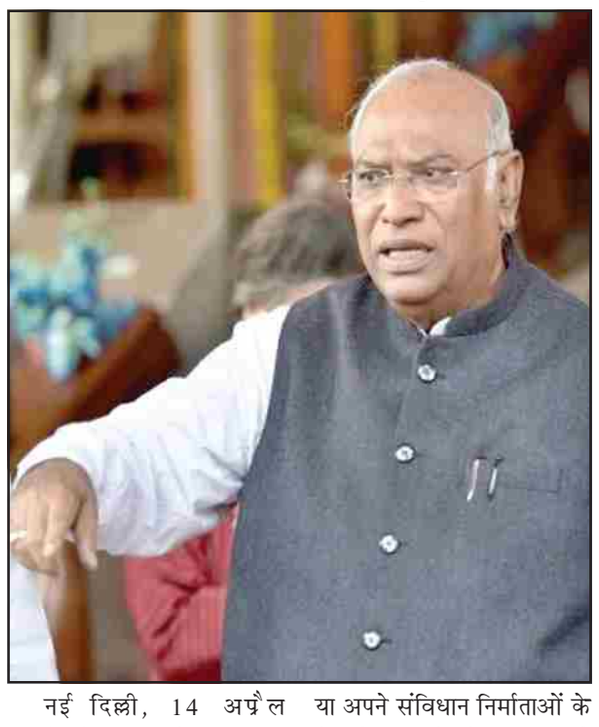

नई दिल्ली, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि हर किसी पर 'देशद्रोही' का ठप्पा लगाना खतरनाक चलन है। उन्होंने एक बयान में कहा- किसी पर भी - चाहे वह विपक्षी दल हों, नागरिक समाज समूह, कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन, न्यायपालिका, मीडिया और आम नागरिक हों, उन्हें 'देशद्रोही' के रूप में ब्रांडिंग करने की संस्कृति खतरनाक प्रवृत्ति है, जो हमारे लोकतंत्र को खत्म कर देगी और हमारे संविधान को नष्ट कर देगी।

कांग्रेस प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि संसद को विपक्ष ने नहीं, बल्कि खुद सत्ता पक्ष ने बहस के बजाय युद्ध के अखाड़े में बदल दिया है। उन्होंने कहा, यह गंभीर आत्मनिरीक्षण का समय है कि क्या हम अपने लोकतंत्र के पतन की अनुमति देंगे और तानाशाही का मार्ग प्रशस्त करेंगे या अपने संविधान निर्माताओं के बेहतरीन आदर्शों को संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। विकल्प हमारे और केवल हमारे पास है।

खड़गे ने शुक्रवार को डॉ बी.आर. अंबेडकर की जयंती पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के चैंपियन के रूप में सराहना की। उन्होंने कहा, वह आर्थिक और सामाजिक रूप से भारत और उसके समाज के परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के प्रति ऑढ़ थे। भारत के संविधान निमार्ता के रूप में हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं।

उन्होंने कहा कि अम्बेडकर ने बड़ी संख्या में मजबूत संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और विभाजनकारी राजनीति को समाप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए।

राज्यपाल ने की .....

जीवन दर्शन में उसकी मूल शक्ति वैज्ञानिक चिंतन था।

राज्यपाल ने कहा कि हमें बाबा साहब के विचारों को प्रचारित प्रसारित करने की अवश्यकता है तभी हम एक सशक्त राष्ट्र निर्माणकर्ता बाबा साहब के सपनों का भारत के सपनों को साकार कर पाएंगे।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यपाल ने एक अति महत्पूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि आज के इस पुनीत अवसर पर भारत के महान विभूति, सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत बाबा साहब के राष्ट्र निर्माण में बहुमूल्य योगदानों को स्मरण करते हुए मैं सिक्किम के राज्यपाल के रूप में सिक्किम के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के प्रतिभावान युवकों में बाबा साहब अंबेडकर के राष्ट्र के प्रति अतुल्य योगदान एवं सामाजिक समरसता के विचारों को जागृत करने और उनके पद चिन्हों का अनुशरण करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता जैसे निबंध लेखन, चित्रकारी आदि के लिए 'गवनर्स बीआर अंबेडकर प्रतिभा कप' की घोषणा करता हूं जिसमें सिक्किम के सरकारी एवं गैर सरकारी सभी विद्यालयों के 9 -12 वीं के छात्र हिस्सा लेंगे और प्रत्येक विजेता टीम व छात्र को एक-एक लाख रुपये की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा एवं अच्छे प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भी प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाएगा।

अम्बेडकर के सपने ....

ही हमने अनुसूचित जाति समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए सिक्किम अत्याचार अधिनियम 2011 की स्थापना की, जो एससी-एसटी के खिलाफ अत्याचार के लिए सबसे सख्त कार्रवाई सुनिश्चित बनाता है। इसके अलावा, एसडीएफ शासनकाल में नौकरी और शिक्षा में एससी के लिए 6 प्रतिशत और एससी ईसाइयों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वहीं पंचायती राज में भी 6 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।

चामलिंगने आगे कहा कि एसडीएफ सरकार के दौरान हमने हर साल मेधावी छात्रों के लिए बीआर अम्बेडकर छात्रवृत्ति शुरू की। तादोंग डारागांव में अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास स्थापित किया गया, जहां राज्य के कोने-कोने से अनुसूचित जाति की छात्राएं काफी कम शुल्क पर रह सकती हैं। इसके अलावा, अन्य समुदाय के सदस्य के साथ विवाह करने पर विवाहित जोड़ों को एकमुश्त अनुदान भी दिया जाता था। उन्होंने कहा, बहरहाल इन सभी के बावजूद समाज में सच्ची समानता हासिल करने के लिए अभी भी लम्बा रास्ता तय करना है। हमारे समाज एवं संस्कृति में गहरी पैठ बनाई हुई सामाजिक बुराइयों और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में डॉ अम्बेडकर की विरासत एक मार्गदर्शक बन सकती है। जरूरत उनके कार्यों को देखते हुए समान भारत की दिशा में उनके पदचिन्हों पर चलने की है।

जनता से सच छिपाने ....

था, लेकिन पिछले चार वर्षों में सीएम गोले के पालतू गुंडों द्वारा विपक्षी नेताओं, युवा कार्यकर्ताओं और नागरिकों के खिलाफ राजनीतिक आतंक मचाया गया है। इतना करने के बावजूद वे बेशर्मी से राज्य की शांति और सौहार्द बिगाड़ने हेतु दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों तक मुख्यमंत्री ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम किया है। ऐसे में भूटिया ने स्वस्थ लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह न होने की बात कहते हुए सिक्किमवासियों से एकजुट होकर इस तानाशाह सरकार को हटाने की अपील की है।

गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में बोले पीएम- अप्रासंगिक हो चुके 2000 कानून किए समाप्त

गुवाहाटी, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में कहा कि हमारे यहां के कई कानूनी प्रावधान ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं। कई ऐसे कानून हैं, जो अप्रसंगिक हो गए हैं। सरकार के स्तर पर हम इनकी निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। हमने ऐसे दो हजार केंद्रीय कानूनों की पहचान कर उनको खत्म कर दिया है। ऐसे 40 हजार से ज्यादा कंप्लांसिस को भी समाप्त कर दिया है।

व्यापार के दौरान आने वाली दिक्कतों को भी दूर किया। सरकार ने केसों को करने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा, टेक्नोलॉजी आज एक पॉवर टूल बनकर उभरी है। सरकार हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का हर संभव उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, गुवाहाटी हाई कोर्ट ऐसे समय में समय में 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है, जब देश की आजादी के भी 75 वर्ष पूरे होना का जश्न मना रहा है। हमारे लिए यह अभी तक के अनुभवों को सहेजना का भी समय है और नये लक्ष्यों के लिए जवाबदेही और जरूरी बदलावों का भी महत्वपूर्ण पड़ाव है। गुवाहाटी हाई कोर्ट की एक अलग विरासत और अपनी एक पहचान रही है। एक ऐसा हाई कोर्ट जिसका दायरा सबसे बड़ा है। असम के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम और नगालैंड यानी तीन अन्य राज्यों की भी सेवा करते हैं। 2013 तक तो सात राज्यों पूर्वोत्तर के साथ राज्य आते थे। इसलिए इन 75 वर्षों के उत्सव में पूरे पूर्वोत्तर की विरासत जुड़ी हुई है।

प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी में हर भारतवासियों के सपने और आकाक्षाएं असीम हैं। इनकी पूर्ति में लोकतंत्र के एक स्तंभ के रूप में हमारी सशक्त और संवेदनशील न्यायपालिका भी भूमिका भी उतनी ही अहम है। हम अपने समाज के लिए वाइब्रेंट, सशक्त और आधुनिक न्याय सिस्टम बनाएं। सपनों को पूरा करने के लिए तीनों अंगों की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही पुराने और अनुपयोगी कानूनों को निरस्त करने की भी जिम्मेदारी है।

125 फीट ऊंची बाबा साहब की मूर्ति का सीएम केसीआर ने किया अनावरण, डॉ. आंबेडकर के पोते भी थे मौजूद

हैदराबाद, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में डॉ. बी आर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम के साथ-साथ डॉ. अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर भी मौजूद रहे।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखते ही पार्टी का नाम बदल दिया था। असल में उन्होंने दशहरा के दिन अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) का नाम बदल कर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) रख दिया था।

राव ने प्रतिमा के स्वरूप की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रतिमा कल्पना से ज्यादा बेहतर बनी है। उन्होंने कहा कि हम देश के गौरव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। इस देश आने वाली पीढ़ियों के लिए संविधान निर्माता के रूप में सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले योद्धा के तौर पर उनकी मेहनत और बलिदान शाश्वत है। केवल दलित ही नहीं, आदिवासी, बहुजन, भारत के लोग जहां भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा वहां बाबसाहेब की महत्वाकांक्षा साकार हुई। हम उनके लिए जितना भी करें कम है।

उन्होंने बताया कि अनावरण के अवसर पर मूर्तिकार 98 वर्षीय पद्म भूषण राम वनजी सुतार कृष्णा को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। उनका कार्यक्रम के दौरान सम्मान किया जाएगा।

राव ने हाल ही में अंबेडकर प्रतिमा के उद्घाटन, नए सचिवालय भवन परिसर के उद्घाटन और अन्य मुद्दों को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि अंबेडकर की प्रतिमा पर शुक्रवार को हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की जाएगी।

केसीआर ने कहा कि डॉ. अंबेडकर की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए राज्य सचिवालय का नाम उनके नाम पर रखा गया है। उन्होंने प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर राज्य के कोने-कोने से आने वाले अतिथियों की सुविधा के लिए सभी इंतजाम करने का निर्देश दिया है। उनके लिए टेंट, पीने के पानी, छाछ आदि की व्यवस्था की गई है। बाबासाहेब को भव्य तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष हेलिकॉप्टर से पुष्पवर्षा की जाएगी। गुलाब, सफेद गुलदाउदी और पान के पत्तों की एक बड़ी माला बनाई गई है।

बता दें, डॉ. अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा पर लगे विशाल पर्दे को हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में बौद्ध भिक्षु भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर खेल-कूद और गीत-संगीत के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन होगा। अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. बी आर अंबेडकर के प्रपौत्र प्रकाश अंबेडकर को आमंत्रित किया गया है। यह समारोह दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा।

यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है कि सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों के 35,000 से अधिक लोग अंबेडकर प्रतिमा अनावरण सभा में शामिल हों। इसलिए राज्य द्वारा संचालित सड़क परिवहन निगम की 750 बसों का संचालन किया जाएगा। हैदराबाद पहुंचने से पहले 50 किमी के दायरे में विधानसभा परिसर में आने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी।

अगला सीएम ममता दीदी का भतीजा नहीं, बीजेपी का होगा : अमित शाह

कोलकाता, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को बंगाल के बीरभूम जिले में पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं गृह मंत्री बीरभूम के सिउड़ी में सभा स्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें एक तारा देकर सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज बीरभूम के सिउड़ी से आज तृणमूल कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता दीदी और उनके भतीजे पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, ममता दीदी का एक मात्र लक्ष्य है अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनना। लेकिन मैं गरंटी देता हूं, उनका यह सपना केवल सपना बन कर ही रह जाएगा। क्योंकि बंगाल का अपना मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा।

उन्होंने कहा, दीदी ने तीन लाख नौकरियां देने का वादा किया था, वह कहां है। आज बंगाल भ्रष्टाचार, गौतस्करी का अड्डा बन गया है। उन्होंने कहा, इनके नेताओं के घर से 21 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ काम चलता रहेगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया, 2024 में बंगाल से 35 लोकसभा सीटों पर भाजपा को जीता कर, इसका ट्रायल दिखा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनना है। उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार बना दीजिए, फिर राम नवमी के जुलूस पर हमला करने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। केंद्रीय योजनाओं पर दीदी अपने नाम का लेबल लगा रही हैं।

इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुवेंदु अधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के साथ बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

गृह मंत्री के दौरे पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव से पहले और रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के बाद वे बंगाल पहुंचे हैं। यह क्षेत्र तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता अणुब्रत मंडल का है, जो पशु तस्करी मामले में इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। सभा के बाद गृहमंत्री शाम को एक सांगठनिक बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ वे विचार-विमर्श करेंगे। बांग्ला नववर्ष के पहले दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। इस साल यह अमित शाह का पहला बंगाल दौरा है।

बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गुरुवार को सभास्थल का दौरा करने के बाद कहा कि गृहमंत्री की यह रैली एतिहासिक होगी। उन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता किस मुंह के साथ गृहमंत्री की सभा का विरोध करेंगे। गृह मंत्री उसी दिन रात के समय वह कोलकाता लौट आएंगे। यहां पार्टी की कोर कमेटी के साथ उनकी अहम सांगठनिक बैठक होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में पंचायत चुनाव में अमित शाह का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

शाह का दौरा, भाजपा के प्रवास अभियान का हिस्सा है। दरअसल, इस अभियान के तहत भाजपा के वरिष्ठ अधिकारी उन क्षेत्रों को मजबूत करेंगे, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में मामूली अंतर से भाजपा की हार हुई थी। भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनावों में बंगाल की कुल 42 सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी।

कांग्रेस ने फिर उठाई जेपीसी जांच की मांग, कहा- अदाणी समूह का चीन से संबंध सामने लाना जरूरी

नई दिल्ली, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। कांग्रेस द्वारा अदाणी समूह के कथित चीन से लिंक और मॉरिस चांग को चीनी नागरिक बताए जाने वाला मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। अब एकबार फिर कांग्रेस ने इस मामले को उठाया है। उन्होंने कहा कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से जांच कराना जरूरी है।

गौरतलब है, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मॉरिस चांग एक चीनी नागरिक हैं। इसके साथ ही पार्टी ने यह दावा किया था कि इस व्यक्ति की कंपनी के अदाणी समूह के कार्यों में जुड़े होने से देश की सुरक्षा को खतरा है। अदाणी समूह के साथ रिश्तों को लेकर चर्चा में आए मॉरिस चांग ने कहा था कि मैं चीनी नहीं ताइवानी नागरिक हूं।

कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि 'हम अदाणी के हैं कौन' के तहत कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए थे। पार्टी ने उनसे उनके पसंदीदा व्यापारिक समूह के चीनी नागरिक चांग के साथ संबंधों के बारे में पूछा था, जो विनोद अदाणी के साथ कई अदाणी समूह की कंपनियों में निदेशक रहे हैं और पनामा पेपर्स में भी उनका नाम सामने आया था। इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए जेपीसी से जांच कराना जरूरी है।

चांग पीएमसी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। उनकी कंपनी अदाणी समूह के लिए बंदरगाहों, टर्मिनलों, रेल लाइनों, पावर लाइनों और अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रही है।

मॉरिस चांग ने चीनी होने के दावे को खारिज करते हुए कहा थी कि वह ताइवान के नागरिक हैं। उनका पासपोर्ट दिखाता है कि वह रिपब्लिक ऑफ चाइना (आरओसी) के नागरिक हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर ताइवान नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि यह चीन से अलग है। हालांकि, पीएमसी के अदाणी समूह के साथ परियोजनाओं पर काम करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया।

पीएमसी पर अदाणी समूह की फर्मों के लिए आयातित उपकरणों का अधिक चालान करने का भी आरोप है। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह ताइवान में एक अच्छी तरह से स्थापित उद्योगपति हैं और वैश्विक व्यापार, शिपिंग, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, शिप-ब्रेकिंग आदि में व्यावसायिक हित हैं। जहां तक अदाणी समूह का संबंध है, मामला न्यायाधीन है और वह इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाया जा रहा है और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। वह पहले ही अपनी नागरिकता के बारे में स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है।

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 01:00 PM
DEAR MEGHNA FRIDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:2 DrawDate on:14/04/23
1st Prize ₹1 Crore/- 62L 10807
Cons. Prize ₹1000/- 10807 (Remaining All Serial & Series)
2nd Prize ₹9000/-
05132 17448 18185 22030 27144 38665 44954 72115 74612 89228
3rd Prize ₹450/-
0366 1063 1135 2260 4104 5663 6963 8002 8028 9931
4th Prize ₹250/-
0988 1092 1327 2443 3663 5587 7046 7285 8368 8600
5th Prize ₹120/-
0021 0121 0296 0334 0453 0502 0577 0620 0637 0813
0877 0934 0972 0981 1164 1395 1423 1492 1790 1886
1912 2152 2159 2209 2275 2417 2479 2560 2679 2912
2992 3297 3424 3518 3672 3690 3780 3843 4044 4082
4114 4249 4259 4455 4458 4501 4527 4567 4854 4868
5030 5237 5264 5269 5311 5405 5448 5490 5892 5898
5969 6036 6158 6177 6239 6265 6270 6283 6402 6428
6824 6833 6844 6871 7109 7321 7744 7868 7871 7957
7982 8136 8201 8212 8278 8372 8509 8673 8954 8964
8999 9014 9077 9089 9112 9286 9354 9515 9525 9917
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 06:00 PM
DEAR MOUNTAIN FRIDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:2 DrawDate on:14/04/23
1st Prize ₹1 Crore/- 81H 64893
Cons. Prize ₹1000/- 64893 (Remaining All Serial & Series)
2nd Prize ₹9000/-
03205 11054 20370 41437 48255 51041 52932 66257 67716 91288
3rd Prize ₹450/-
0588 1032 4683 5016 6892 7220 7665 7935 8527 9677
4th Prize ₹250/-
0206 0349 0949 2224 3066 6146 7883 8425 8579 8894
5th Prize ₹120/-
0142 0300 0351 0388 0551 0623 0687 0773 0827 0851
0888 0907 0938 0963 1078 1456 1596 1665 1674 1885
1947 1984 1992 2150 2153 2201 2283 2292 2328 2526
2539 3286 3297 3317 3445 3551 3626 3687 3692 3759
4048 4085 4120 4162 4305 4467 4543 4671 4763 4815
4854 4946 5007 5187 5260 5306 5383 5562 5670 5824
5914 6024 6117 6190 6206 6305 6327 6685 6820 6998
7010 7059 7169 7329 7482 7483 7501 7611 7748 7860
8007 8162 8169 8230 8419 8428 8656 8935 9022 9110
9269 9324 9342 9414 9482 9549 9558 9707 9839 9948
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 08:00 PM
DEAR SEAGULL FRIDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:2 DrawDate on:14/04/23
1st Prize ₹1 Crore/- 40J 50300
Cons. Prize ₹1000/- 50300 (Remaining All Serial & Series)
2nd Prize ₹9000/-
04704 09134 12770 16945 22933 38148 42244 68820 70694 84449
3rd Prize ₹450/-
2200 2625 4389 4506 5735 5754 6781 6809 7131 8130
4th Prize ₹250/-
2320 3332 3973 4444 5673 7215 8193 8962 9305 9469
5th Prize ₹120/-
0090 0601 0719 0731 0759 0792 1354 1380 1444 1452
1518 1540 1764 1796 1998 2039 2214 2235 2353 2387
2495 2496 2516 2853 2913 3007 3082 3133 3210 3248
3249 3348 3407 3611 3838 3861 3865 3986 4109 4157
4224 4254 4277 4367 4404 4743 4785 4924 4957 5049
5064 5076 5086 5472 5633 5634 5709 5849 5855 5879
5975 6068 6086 6093 6165 6237 6255 6265 6328 6470
6504 6575 6658 6742 6800 6946 6995 7156 7239 7289
7290 7361 7394 7617 7619 7637 7640 7652 8052 8132
8247 8427 8533 8810 9046 9071 9365 9485 9659 9841
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

फायरिंग ने खड़े किए कई सवाल

पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर बुधवार तड़के हुई फायरिंग की घटना जितनी गंभीर है, उतनी ही रहस्यमय भी साबित हो रही है। सेना के चार जवानों की मौत तो एक बड़ा सदमा है ही, उससे भी बड़ी बात यह है कि इस मिलिट्री स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ऐसे सवाल उठे हैं, जो हमारी सेना की छवि के अनुरूप नहीं लगते। शुरू में ही कहा गया कि यह कोई आतंकी हमला नहीं है, बाहर से कोई नहीं आया। इसी क्रम में इसे फ्रैक्ट्रिसाइड यानी भ्रातृहत्या बताया गया। यानी किसी वजह से कोई नाराज सैनिक खुद पर काबू नहीं रखा पाया और गुस्से में फायरिंग कर उसने साथी जवानों की जान ले ली। लेकिन दो दिन पहले इंसास राइफल और उसकी गोलियां गायब हुई थीं, जिनका इस हमले में इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है।

अगर यह बात सही है तो इसका मतलब यह एक सुनियोजित घटना थी। यह भी कहा जा रहा है कि हमलावर एक से ज्यादा थे। कुर्ता-पायजामा पहने दो नकाबपोशों को जंगल की ओर भागते देखा भी गया। यह बात भी इस घटना के फ्रैक्ट्रिसाइड होने की संभावना को खंडित करती है। दूसरी बात यह कि जब हमलावरों को पकड़ा नहीं जा सका है और न ही उनकी पहचान हो पाई है तो फिर यह बात दावे से कैसे कही जा सकती है कि इसके पीछे कोई आतंकी साजिश नहीं हो सकती? क्या यह हो सकता है कि सेना से जुड़े एकाध लोगों के जरिए इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया हो? क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिन हमलावरों को जंगल की ओर भागा माना जा रहा है, वे मौका निकालकर किसी तरह वापस कैंट में आ गए हों।

अगर उनकी पहचान नहीं हुई है तो एक बार अन्य जवानों में मिल जाने के बाद उन्हें अलग करना मुश्किल होगा। कुछ और भी तथ्य हैं जिनके ठोस स्पष्टीकरण नहीं मिल रहे।

कहा जा रहा है कि इंसास राइफलों के लापता होने की रिपोर्ट भी मंगलवार को दर्ज कराई गई, लापता होने के दो दिन बाद। यही नहीं, फायरिंग की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने में भी असाधारण देरी देखी गई। यह घटना तड़के 4.30 बजे की है, लेकिन पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दोपहर 2.56 बजे दी गई। पुलिस डायरी में इस घटना की पहली एंट्री दिन में 3.03 बजे हुई बताई गई है।

चूंकि यह देश की सुरक्षा और सेना की छवि से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण मसला है इसलिए इसमें किसी तरह की कयासबाजी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इन पहलुओं को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। खबरों के मुताबिक सेना और सरकार दोनों ने इसे काफी गंभीरता से लिया है और इस पूरे प्रकरण के हर पहलू पर बारीकी से जांच करवाई जा रही है। उम्मीद की जाए कि जांच के बाद न केवल सभी सवालों के जवाब मिलेंगे बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में आई खामियों को भी दुरुस्त किया जाएगा।

पाकिस्तान में संविधान की स्वर्ण जयंती पर सियासी संकट

मरिआना बाबर

जैसा कि वे कहते हैं-देर आए दुरुस्त आए। हाल ही में पाकिस्तान के हिंदू समुदाय के लिए एक अच्छी खबर आई, जिसकी वे वर्षों से मांग कर रहे थे। इस्लामाबाद प्रशासन ने 2017 के हिंदू विवाह अधिनियम के नियमों और प्रक्रियाओं की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। यह एक ऐसा कानून है, जो पाकिस्तानी हिंदू को अपनी शादी और सभी प्रासंगिक अनुष्ठानों का जश्न मनाने का अधिकार देता है, जो सार्वजनिक रूप से विवाह समारोह से जुड़े हैं। यह एक बुनियादी स्वतंत्रता है, जिसका हर किसी को आनंद लेना चाहिए। यह दुखद है कि इस सांविधानिक अधिकार को मूर्त रूप देने में इतना समय लगा।

हालांकि खुद हिंदू समुदाय और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कानून पूरे देश में, विशेष रूप से सिंध में लागू हो, जहां सबसे अधिक संख्या में हिंदू रहते हैं। कानून अब हिंदू जोड़े को विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकार देता है, ताकि विवाह को पंजीकृत किया जा सके और वैध समझा जाए।

पाकिस्तानी महिलाओं के लिए यह घोषणा भी अच्छी खबर है कि ऑस्कर विजेता निर्देशक शरमीन ओबैद-चिनॉय को स्टार वार्स फ्रेंचाइजी में फिल्म निर्देशित करने के लिए नामित किया गया है, जो न सिर्फ यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला हैं, बल्कि पहली अश्वेत भी हैं। वह पहले ही डिज्नी टीवी शो के कई एपिसोड और कई वृत्तचित्र निर्देशित कर चुकी हैं। लेकिन जैसा कि हम इस क्षेत्र में एक अन्य पाकिस्तानी महिला और उनकी अनेक बहनों की सफलता का जश्न मना रहे हैं, मैं अफगानिस्तान की बहनों के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पा रही हूं। क्रूर तालिबानी शासन द्वारा दिन-ब-दिन उनका दमन किया जा रहा है और हालांकि दुनिया के हर देश में आवाज उठाई गई है, लेकिन इससे तालिबान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिन्होंने इस सप्ताह उनके पार्कों और रेस्तरांओं में जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

पाकिस्तान इस हफ्ते अपने संविधान की स्वर्ण जयंती मनाने में व्यस्त है, जो सभी राजनीतिक दलों द्वारा आम सहमति का दस्तावेज है, और जो लंबे समय तक सैन्य शासन एवं स्वयं सांसदों द्वारा इसे बार-बार संशोधित करने के बावजूद बरकरार है। लेकिन एक बहुत ही कमजोर लोकतंत्र वाले देश में यही एकमात्र दस्तावेज है, जो संघ और प्रांतों की संरचना को एक साथ जोड़े हुए है। हालांकि ये उत्सव ऐसे समय में हो रहे हैं, जब सबसे बड़े सांविधानिक संकटों में से एक महीने भर से ज्यादा समय से सुर्खियों में है।

परंपरागत रूप से पाकिस्तान में राजनीतिक या सांविधानिक संकट में हमेशा सुरक्षा प्रतिष्ठान शामिल रहता है, क्योंकि वह हमेशा राजनीतिक दखल देने और अपनी शक्ति का दुररुपयोग करने की कोशिश करता है और वह भी व्यापक राष्ट्रीय हित के नाम पर। लेकिन इस बार सांविधानिक संकट शाहबाज शरीफ सरकार और मुल्क के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल के बीच टकराव को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के कई न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय में 'वन मैन शो' चलाने और अनगिनत स्वत: संज्ञान नोटिस द्वारा न्यायपालिका के अनावश्यक राजनीतिकरण करने के लिए प्रधान न्यायाधीश की आलोचना की है।

सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच टकराव का मुख्य बिंदु यह है कि सरकार अलग चुनाव नहीं कराना चाहती है, बल्कि देश में अक्टूबर में आम चुनाव कराना चाहती है। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ की पंजाब प्रांत में सरकार है। पंजाब और खैबर पख्तुनख्वा सरकार ने कुछ समय पहले दोनों प्रांतों की विधानसभाएं भंग कर दी। और अब संविधान के अनुसार 90 दिनों के भीतर चुनाव होने हैं।

मामले-दर-मामले प्रधान न्यायाधीश का पक्षपात देखा जा सकता है, जहां वह पीटीआई प्रमुख इमरान खान को बार-बार राहत दे रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं, लेकिन उनमें से हरेक मामले में उन्हें जमानत मिल जाती है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके अलावा, स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करके और पंजाब व खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव कराने का आह्वान कर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टत: इमरान खान का समर्थन किया है।

सदन के नेता शाहबाज शरीफ इस मुद्दे को संसद में ले गए हैं और कहा है कि वर्तमान में नकदी की तंगी वाला कोई भी देश अलग चुनाव कराने का जोखिम नहीं उठा सकता है। सुरक्षा बलों ने भी कहा है कि वे आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में व्यस्त हैं और अपने अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए नहीं छोड़ सकते। संसद ने एक प्रस्ताव के जरिये इस पर सहमति जताई और सर्वोच्च न्यायालय को संदेश दिया कि वह राजनीति में शामिल न हों और यह तय करना केवल मुख्य चुनाव आयुक्त का काम है कि चुनाव अलग से कराए जा सकते हैं या नहीं।

इस संदर्भ में राजनीतिक विश्लेषक एवं लेखक जाहिद हुसैन कहते हैं, 'निश्चित रूप से हमारे सांविधानिक इतिहास के 50 साल जश्न मनाने लायक हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है संविधान का वास्तविक रूप से काम करना। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ है। मुल्क अब भी एक रास्ता तलाशने के लिए संघर्ष कर रहा है। शक्ति संघर्ष ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पहले की तुलना में बहुत कमजोर कर दिया है, जिससे संविधान के एक बार फिर पटरी से उतरने की आशंका बढ़ गई है।'

बेहद वैध आलोचना का एक और बिंदु यह है कि जब प्रधान न्यायाधीश किसी राजनीतिक मामले की सुनवाई के लिए पीठ का गठन करते हैं, तो अपने बाद के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को उसमें शामिल करने से बचते हैं, जो सितंबर में पदभार संभालेंगे, यानी जस्टिस फैज ईसा। प्रधान न्यायाधीश उन न्यायाधीशों को पीठ में शामिल करते हैं, जो पंजाब से हैं, जबकि छोटे प्रांतों के न्यायाधीशों को उससे बाहर रखते हैं।

पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को इन शब्दों में बखूबी अभिव्यक्त किया गया है- 'सुप्रीम कोर्ट में प्रतिदिन होने वाले नाटक ने न केवल राज्य के तीसरे स्तंभ को विधायी और कार्यकारी अंगों के साथ सीधे टकराव की स्थिति में ला दिया है, बल्कि देश में व्याप्त अनिश्चितता और भ्रम को भी बढ़ा दिया है। अगर कुछ है, तो वह कि शेष समाज की तरह सर्वोच्च न्यायपालिका भी राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत और बंटी हुई है।'

डॉलर का घटता वैश्विक दबदबा और रुपये का बढ़ता रुतबा

पी. एस वोहरा

आर्थिक जगत में इन दिनों इस बात पर गहन विमर्श चल रहा है कि आने वाले समय में अमेरिकी मुद्रा डॉलर का वैश्विक दबदबा कम हो जाएगा। चर्चाओं के इस दौर में कई दूसरे देशों की मुद्राओं का नाम वैश्विक मुद्रा के रूप में लिया जा रहा है। इसमें चीन की मुद्रा युआन का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। दूसरी तरफ यह भी सोच है कि आगामी अगस्त में ब्रिक्स देशों की बैठक में निश्चित रूप से डॉलर के विरुद्ध किसी नई मुद्रा का उदय होगा। इस चर्चा की शुरुआत तब हुई, जब यह देखा गया कि पिछले कुछ अर्से से अमेरिकी मुद्रा डॉलर का संग्रहण बड़ी तेजी से घट रहा है।

इस संदर्भ में आईएमएफ की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1999 तक जहां वैश्विक मुद्रा संग्रहण में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी करीब 70 फीसदी से अधिक थी, वह वर्ष 2022 में घटकर 59 फीसदी रह गई है। डॉलर के बाद सबसे अधिक संग्रहण यूरो का है।

अगर डॉलर का वैश्विक दबदबा कम होता है या उसके विकल्प के रूप में किसी अन्य मुद्रा को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलती है, तो निश्चित रूप से यह पिछली एक शताब्दी में अमेरिका की वैश्विक साख में बहुत बड़ी गिरावट होगी। इसके लिए स्पष्ट रूप से अमेरिका की आर्थिक नीतियां ही दोषी हैं। सभी मुल्क अमेरिकी डॉलर की आक्रामकता से सदैव परेशान रहते हैं। मसलन, इन दिनों अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी से डॉलर वैश्विक स्तर पर बहुत मजबूत हुआ, जिससे सभी देशों की मुद्राएं अत्यंत कमजोर हुईं। इससे सभी देशों के आयात महंगे हुए, जिसने अंतत: घरेलू बाजारों में तेजी से महंगाई बढ़ाई। इसलिए कई मुल्क अमेरिका के बजाय अब दूसरे विकसित देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं तथा उन मुल्कों की विदेशी मुद्राओं के संग्रहण को प्राथमिकता दे रहे हैं।

वास्तव में यह चर्चा अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का ही हिस्सा है। रूस-यूक्रेन युद्ध में वैश्विक स्तर पर अमेरिकी रुख को रूस और चीन, दोनों मिलकर मजबूती से जवाब देना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले चीन ने अमेरिकी डॉलर के अपने भारी-भरकम संग्रहण को अपनी मुद्रा युआन में परिवर्तित किया। फिर रूस द्वारा वैश्विक स्तर पर इस बात को प्रमुखता से उठाया जाने लगा कि आने वाले समय में चीन की मुद्रा युआन को डॉलर की जगह लेनी चाहिए। हालांकि वैश्विक स्तर पर कुल विदेशी मुद्रा भंडार में चीन की मुद्रा का हिस्सा मात्र पांच फीसदी के आसपास ही है।

आगामी अगस्त में होने वाली ब्रिक्स देशों की बैठक में डॉलर के विरुद्ध अन्य मुद्रा का विकल्प अवश्य चर्चा में रहेगा। लेकिन ब्रिक्स बैठक में भारत कभी भी युआन को डॉलर के विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसके पीछे विभिन्न आर्थिक तथा राजनीतिक कारण हैं। चीन व रूस की प्रगाढ़ दोस्ती के पीछे मुख्य निशाना भारत है। इसलिए ब्रिक्स के अंतर्गत चीन की मुद्रा को डॉलर के विकल्प के रूप में शायद ही देखा जाए।

अब अगर भारत के विदेशी मुद्रा संग्रहण की बात की जाए, जो इन दिनों 530 अरब डॉलर के आसपास है, तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर का ही है। भारत की आर्थिक नीतियों का झुकाव अमेरिका की तरफ ज्यादा रहता है। हालांकि अमेरिकी डॉलर की आक्रामकता से कई बार भारतीय शेयर बाजार अचानक गिर जाता है और घरेलू बाजार में महंगाई बढ़ जाती है। रही बात भारतीय रुपये के डॉलर का विकल्प बनने की, तो अभी यह आसान नहीं है।

गौरतलब है कि किसी भी देश की मुद्रा को वैश्विक मुद्रा के रूप में पहचान हेतु उस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था होना व आर्थिक नीतियों में प्रगतिशीलता जरूरी है। भारत में ये दोनों बातें हैं और भारत विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, परंतु अभी उसे एक लंबा सफर तय करना है, क्योंकि भारत का निर्यात बहुत कम है। इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि भारत किसी अन्य मुद्रा को डॉलर के विकल्प के रूप में समर्थन देगा।

मिशन लाइफ का केंद्र है जल प्रबंधन

गजेंद्र सिंह शेखावत

जलवायु परिवर्तन की उत्पत्ति का पता 'ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स' नामक एक आर्थिक सिद्धांत से लगाया जा सकता है, जो बताता है कि जब व्यक्तियों के पास एक समान संसाधन तक पहुंच होती है, तो वे अपने हित में कार्य करते हैं, दूसरों पर उनके प्रभाव को देखते हुए स्वार्थी निर्णय लेते हैं। पृथ्वी हमारा साझा संसाधन है, और इसी मानवीय प्रवृत्ति ने हमें जलवायु परिवर्तन के रूप में ज्ञात इस खतरे में धकेला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 ग्लासगो में आयोजित सीओपी-26 में इस पर प्रकाश डाला। एक पहलू जिसे उन्होंने समझाया, वह थी, एलआईएफई (लाइफ) की अवधारणा यानी 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली'। मिशन लाइफ का केंद्र जल है।

जब भारत ने एक दिसंबर, 2022 को जी-20 की अध्यक्षता संभाली, तो हमने 'वसुधैव कुटुंबकम' के आदर्श वाक्य के साथ 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के दृष्टिकोण को साझा किया। यदि दुनिया को जलवायु परिवर्तन के संकट से जीतना है, तो जी-20 देशों को अत्यधिक प्रयास करना होगा, क्योंकि दुनिया का 80 फीसदी उत्सर्जन इन देशों के कारण होता है। यद्यपि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव व्यापक है, यहां जल संसाधन प्रबंधन की चर्चा की जा रही है।

भारत तकनीकी अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और अत्याधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जल संसाधन विकास और प्रबंधन में जी-20 सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का मानना है कि जल हमारे विकास प्रतिमान के केंद्र में होना चाहिए।

27-29 मार्च, 2023 के दौरान गांधीनगर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) की दूसरी बैठक में जलशक्ति मंत्रालय के नेतृत्व में जल संसाधन प्रबंधन पर एक कार्यक्रम था। जल सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराने के लिए एकत्रित देशों के साथ, भारत ने फिर से पुष्टि की कि उसकी प्राथमिकताएं, नीति और कार्य एसडीजी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित रूप से जुड़े हैं। जल संसाधनों के एकीकृत और सतत उपयोग/पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, जल निकाय पुनरुद्धार, नदी संरक्षण, वर्षा जल प्रबंधन आदि विविध विषयों पर कई प्रस्तुतियां दी गईं, जो सभी जी-20 सदस्यों के लिए बहुत मूल्यवान होंगी।

मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने अपने 1.4 अरब लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई पहल की है। देश में जल प्रबंधन के लिए अधिक तालमेल और सामंजस्य रखने के लिए एकीकृत जलशक्ति मंत्रालय का सृजन किया गया था।

दुनिया के सबसे बड़े पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम जल जीवन मिशन के माध्यम से, आज 11.6 करोड़ से अधिक घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है। हाल के अध्ययनों के अनुसार, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता से पांच वर्ष से कम आयु के 1.36 लाख बच्चों का जीवन बचाया जा सकेगा। हमारे अन्य प्रमुख अभियान, स्वच्छ भारत अभियान ने 10 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण से भारत को 100 फीसदी खुले में शौच से मुक्त बना दिया, जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार, तीन लाख बच्चों के जीवन को बचाया।

भारत ने जलवायु लचीलेपन के लिए रणनीतियों के माध्यम से जल संसाधन विकास पर किए गए कार्यों को भी साझा किया, जिसमें महत्वपूर्ण जल भंडारण के बुनियादी ढांचे और भागीदारी, भूजल के बेहतर प्रबंधन के लिए बांध पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने भारत की प्राचीन जल प्रबंधन प्रथाओं को देखने के लिए गुजरात के अडालज वाव में बावड़ी का भी दौरा किया। इसके बाद साबरमती साइफन संरचना का दौरा किया, जो एक आधुनिक इंजीनियरिंग चमत्कार है, जिसने चुनौतीपूर्ण जल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को डिजाइन और निष्पादित करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया। दूसरी ईसीएसडब्ल्यूजी बैठक एक स्थायी भविष्य की दिशा में जी-20 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लोहे को जीवन से जोड़तीं स्त्रियां

शेफाली मार्टिन्स

कृषि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। कृषि के लिए औजारों की उपयोगिता स्वयंसिद्ध है। किसानों को ये औजार लोहार प्रदान करते हैं। लोहार प्राचीन काल से ही लोहे की धातु को अलग-अलग आकार देकर औजार गढ़ते आ रहे हैं। लेकिन गड़िया लोहारों का समुदाय आज भी गुमनामी के अंधेरे में है। वे अपने काम में पारंपरिक ज्ञान के साथ वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करते रहे हैं, वह भी बिना कभी स्कूल गए। इस समुदाय की महिलाएं भी पुरुषों के बराबर इस काम को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी निभा रही हैं।

राजस्थान में अजमेर-जयपुर हाई-वे के किनारे पारसोली गांव में गड़िया लोहारों का एक गांव घोर गरीबी में जीवन-यापन कर रहा है। इसी कस्बे की 60 वर्षीय डाली गड़िया लोहार कहती हैं, 'हमें नहीं पता कि स्कूल कैसा दिखता है? हमने पंद्रह साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। हम अपने माता-पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठकर लोहे का सामान बेचने एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। जमाना बदल गया है, लेकिन हमारे हालात नहीं बदले।' ये लोहार मूल रूप से मेवाड़ के थे और शासकों के लिए हथियार बनाते थे। जब महाराणा प्रताप ने अपना राज्य खो दिया, तो लोहारों ने भी खानाबदोशों की तरह जीने की कसम खाई।

जीवन-यापन के लिए वे सामान बनाकर बैलगाड़ी पर उसे गांव-गांव बेचते रहे। इस बैलगाड़ी की वजह से उन्हें गड़िया लोहार कहा जाने लगा। लोहारों के इस समुदाय में महिलाएं धातु को औजार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुरुष जहां अंगारों को गर्म करके लोहे पर प्रहार करता है, वहीं महिला पहले अंगारों को पंखा करती हैं और फिर पुरुष के साथ मिलकर धातु को आकार देने में मदद करती हैं। यह कड़ी मेहनत और बहुत कठिन प्रक्रिया है। ये महिलाएं बचपन से ही इस काम को सीखती हैं। महिलाएं सामान बनाने के अलावा गांव-गांव, मेला-दर-मेला जाकर भी अपना उत्पाद बेचती हैं। वे चिमटा, छलनी, दांतली (हाथ की आरी), कुल्हाड़ी, हंसिया और कुदाल बनाती हैं। सामान बनाने के लिए लोहा और कोयला शहर से खरीदती हैं।

इनमें से अधिकांश का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पिछले एक दशक से एक ही जगह पर बसने के कारण अब उनके बच्चे पास के एक सरकारी स्कूल में जाते हैं। उनके काम में कई खतरे भी शामिल हैं। न केवल धधकती आग के सामने उन्हें घंटों बैठना पड़ता है, बल्कि औजार बनाने के दौरान चोट लगने की भी काफी आशंका रहती है। कड़ी मेहनत के बावजूद इन महिलाओं की कोई निश्चित दैनिक आय नहीं है। बड़े पैमाने पर मशीनीकरण ने उन्हें लाभ से वंचित कर दिया है। अब मशीन से बने आधुनिक औजार मौजूद हैं, जो बहुत सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। ऐसे में इनके बनाए औजारों को भला कोई क्यों खरीदेगा।

अब वे सड़क किनारे बैठकर ताले, जंजीर, रसोई के चाकू, घंटियां, चम्मच, चूहेदानी आदि बेचती हैं, जिनसे उन्हें बहुत कम मुनाफा होता है। कमला गड़िया लोहार कहती हैं, हम 20,000 रुपये का सामान खरीदते हैं, पर हमारी कुल कमाई सिर्फ 2,000 रुपये होती है। इस मंहगाई के दौर में महीने में दो-तीन हजार रुपये की कमाई से क्या हो सकता है!

संतोष गड़िया लोहार की भी यही कहानी है। वह कहती हैं, 'हम एक सामान से पांच से दस रुपये ही कमाते हैं। हम कुछ सामान खुद बनाते हैं, और कुछ बेचने के लिए बाजार से खरीदते हैं। मशीनीकरण से हमारा पारिवारिक व्यवसाय प्रभावित हुआ है।' मेले हस्तशिल्प के प्रचार-प्रसार के महत्वपूर्ण स्थल हैं, पर इन लोहारों के लिए यह लाभप्रद नहीं है। पुष्कर मेला भी अब इनके लिए लाभदायक नहीं रहा है।

मेले के आयोजक उनसे प्रति फुट किराये के रूप मे 3,000 रुपये लेते हैं, फिर उन्हें मेले में स्थायी जगह नहीं मिलती है। सामान बिके या न बिके, किराया तो देना ही पड़ता है। यही कहानी क्षेत्र के दूसरे प्रमुख मेले 'अजमेर शरीफ में उर्स मेले' की है।

गड़िया लोहार समुदाय की ये मेहनती महिलाएं उस दिन का इंतजार कर रही हैं, जब उनके बनाए सामान एक बार फिर से लोकप्रिय होंगे और वे अच्छी कीमत पर बिकने लगेंगे।

2024 चुनाव को लेकर लिखी जा चुकी स्क्रिप्ट : सीएम नीतीश

पटना, 15 अप्रैल (का.सं.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को यहां भाजपा नीत केंद्र सरकार पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो लोग उसे (भाजपा) वोट देंगे वे खुद को और देश को बर्बाद करेंगे तथा जो हमें वोट देंगे, वे अपना, देश और राज्य का भला सुनिश्चित करेंगे। पटना स्थित जनता दल (यूनाइटेड) मुख्यालय में डॉ आंबेडकर जयंती के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा कि मैं विपक्षी एकता बनाने की दिशा में काम कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के खिलाफ गठबंधन बनाने को लेकर सभी विपक्षी दल एकजुट हैं।

उन्होंने कहा कि मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें (भाजपा को) वोट देंगे, वे खुद को और देश को बर्बाद करेंगे तथा जो हमें वोट देंगे, वे अपना, देश और राज्य का भला सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनका एकमात्र लक्ष्य भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्ष को एकजुट करने के वास्ते काम करना है। जदयू के शीर्ष नेता नीतीश ने कहा कि मैंने दिल्ली में कांग्रेस और वाम दलों सहित कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। हमारी बहुत सकारात्मक और रचनात्मक मुलाकात हुई। अब मैं अन्य गैर-भाजपा दलों से बात करूंगा और देश भर के दौरे पर जाऊंगा। विपक्षी दलों को एकजुट करना ही एकमात्र लक्ष्य है और इसके लिए हर नेता काम करेगा।

नीतीश ने आरोप लगाया कि भाजपा लोगों को धार्मिक आधार पर बांटकर देश को तोड़ने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वे (भाजपा) इतिहास को फिर से लिखने के लिए बेताब हैं। लोग जानते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या किया। आजादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान था? वे केवल देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पूरे देश से मिटाने की जरूरत है। नीतीश ने कहा कि लोगों को ऐसी ताकतों से सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने राजद के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का विरोध जताते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियां उनके (राजद नेताओं) लिए तब से परेशानी पैदा कर रही हैं, जबसे हम नई राज्य सरकार बनाने के लिए एक साथ आए। अन्य राज्यों में भी गैर-भाजपा नेताओं के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई शुरू की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में अपने दो दिनों के प्रवास के दौरान नीतीश और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इसके अलावा, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई अन्य विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात की। नीतीश कुमार उसके बाद से लगातार बीजेपी पर हमले कर रहे हैं।

उन्होंने साफ कर दिया है कि लोग यदि बीजेपी को वोट देंगे, तो वे अपना ही नाश करेंगे। नीतीश कुमार अक्रामक तरीके से बीजेपी पर हमलावर हैं। इधर, बीजेपी नेता भी लगातार उनके दिल्ली दौरे को लेकर हमला कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने यहां तक कह दिया है कि सजायाफ्ता से आशीर्वाद लेकर नीतीश भ्रष्टाचारियों का गठबंधन तैयार कर रहे हैं।

नियोजित शिक्षकों से बोले सीएम नीतीश- पढ़ाने का काम कीजिए... आमदनी हम बढ़ाएंगे

पटना, 14 अप्रैल (का.सं.)। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर सियासत जारी है। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बनाई गई नई नियमावली को लेकर सियासी रार जारी है। इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पहले से काम कर रहे 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा और वेतन-भत्ता नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि पुराने वाले शिक्षक अपनी जगह पर बने रहेंगे। वे पंचायती राज और नगर निकाय के कर्मचारी बने रहेंगे। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग पढ़ाएंगे उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी।

दरअसल, बिहार सरकार ने इसी सप्ताह शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाई है। अब नई नियमावली के तहत ही बिहार में शिक्षकों की बहाली होगी। नई नियमावली के तहत बहाल किए गए शिक्षक राज्यकर्मी होंगे और उन्हें उसी मुताबिक वेतन-भत्ता और सुविधाएं मिलेंगी। कैबिनेट से नई नियमावली पास होने के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि पहले से नियुक्त शिक्षकों को भी राज्यकर्मी बनने का मौका मिलेगा। वे भी बीपीएससी की परीक्षा पास कर राज्यकर्मी बन पाएंगे। इसके बाद से ही बिहार में सियासत तेज हो गई। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर जारी सियासत के बीच नीतीश कुमार ने पहली बार प्रतिक्रिया दी।

शुक्रवार को जेडीयू कार्यालय में आयोजित बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार ने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली का फैसला लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जो पहले से शिक्षक हैं, उनका भी वेतन बढ़ाएंगे। उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षक बहाली पर लोग क्या-क्या बोल रहे हैं। सात निश्चय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि 2015 में इसको लागू किया गया। जब हमलोग साथ आए (बीजेपी) तो सबने स्वीकारा। फिर अलग हुए तो सब कुछ के कुछ बोल रहे हैं।

नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बिहार में सात पार्टियों की सरकार है। हम लोगों ने तय कर लिया है कि आगे जो भी बहाली करेंगे सरकारी बहाली करेंगे। दो लाख से अधिक बहाली होने वाली है। इसी साल सब करने वाले हैं। बिहार सीएम ने आगे कहा कि जितने लोग पहले से हैं, उनको भी हम रहने देंगे। उनकी भी हम आमदनी बढ़ाएंगे।

पटना में चेकिंग पॉइंट जलाने का आरोपी गिफ्तार

पटना, 14 अप्रैल (का.सं.)। बीते दिनों पूर्व बिहटा-आरा एनएच मुख्य मार्ग में बिहटा थाना क्षेत्र के लेखन टोला गांव के पास जिला खनन विभाग द्वारा अवैध बालू एवं ओवरलोडिंग को लेकर बनाए गये चेकिंग पाइंट को जलाने के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पासिंग गिरोह के मुख्य सदस्य को ब्लैक स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार युवक की पहचान बिहटा थाना क्षेत्र के हिरावनपुर पकड़ी गांव निवासी रजनीकांत उर्फ विक्की कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि लम्बे समय से विक्की पासिंग गिरोह का सक्रिय सदस्य रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियों के चालकों से मोटी रकम लेकर लग्जरी गाड़ी से पासिंग कराने का काम करता था। पासिंग के धंधे से उसने करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर रखी है। हाल ही में उसने कीमती ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी लिया है। जिसपर नंबर ख़लेट पर गाड़ी नंबर को यादव के स्टाइल में लिखा रखा है।

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी से कड़ी पूछताछ की। उसने अपने जुर्म को स्वीकार किया है। ज्ञात हो की गुरुवार की देर रात बिहटा -आरा एनएच मूर्ख मार्ग में थाना क्षेत्र के लेखन टोला गांव के समीप जिला खनन विभाग द्वारा अवैध ओवरलोडिंग वं अवैध बालू को रोकने को लेकर चेकिंग पॉइंट बनाया गया था। जिससे बालू माफिया और पासिंग गिरोह के सदस्यों ने चेकिंग पॉइंट को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में जिला खनन पदाधिकारी ने लिखित शिकायत बिहटा थाना में दर्ज करवाया था। जिसके आधार पर पुलिस करवाई में जुट गई थीं।

थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि एक दिन पूर्व रात में जिला खनन विभाग के द्वारा अवैध बालू वाहन की चेकिंग के लिए बनाया गए चेक पोस्ट को पासिंग गिरोह के सदस्यों ने आग के हवाले कर दिया था। जिसके मुख्य सदस्य को स्कार्पियो के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। साथ ही अन्य सदस्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

नई नियमावली से शिक्षा की क्वालिटी बढ़ेगी, शिक्षकों का विरोध करना गलत : शिक्षा मंत्री

पटना, 14 अप्रैल (का.सं.)। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली से शिक्षा की क्वालिटी बढ़ेगी। इसके साथ ही चयनित शिक्षक राज्यकर्मी होंगे। नियोजित शिक्षकों की ओर से विरोध किया जा रहा है, जो गलत है। परीक्षा में रोज पढ़ाने वाले सवाल ही पूछे जाएंगे।

शुक्रवार को कार्यालय में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की जयंती समारोह आयोजित की गई थी। इस समारोह में शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, 'भगवान भी शिक्षकों को वेतनमान नहीं दे सकता'।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि कोई रोजगार नहीं मिलता है तो युवा बीएड कर लेते हैं। नेट की तैयारी में काफी मेहनत करनी पड़ती है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि युवकों ने शिक्षक बनने के लिए बीएड करने के साथ साथ टीईटी भी पास किया। अब एक परीक्षा से क्यों घबरा रहे हैं ? उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि आज गौरवशाली दिन है। बाबा साहेब ने संविधान का निर्माण किया। उस संविधान पर कोई आंच आता है तो संघी ताकतों से लोहा लेना पड़ेगा। यही आज के दिन का संकल्प है।

प्रो. चंद्रशेखर ने नई शिक्षक नियमावली में बदलाव के सवाल पर कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सरकार का संकल्प है। बिहार के शिल्पकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का मानना है कि ज्ञान की भूमि की विरासत को वापस लाना है। इसको लेकर ही नई नियमावली लाई गई है। इसमें कोई गलती निकालते हैं, जो उचित नहीं है।

चंद्रशेखर ने कहा कि जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, उनका काम शिक्षा देना है। नियोजित शिक्षक जिस कोर्स को हर दिन बच्चों के बीच पढ़ाते हैं, उसी कोर्स से कुछ सवाल नियमित होने के लिए परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें गलत क्या है ? उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार ने बड़ी बीमारी दूर किया है। नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी के दर्जे प्राप्त करेंगे। उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी। अच्छी सैलरी मिलेगी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देनी है। बिहार के बेरोजगारों के लिए सरकार चिंतित है। उन्होंने कहा कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो नफरतवादियों की नींद हराम हो गई। संघियों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है। अब वे चिंता में बड़बड़ा रहे हैं।

कोई आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता : सम्राट चौधरी

2024 में विपक्षी एकता होगी सफल : मांझी

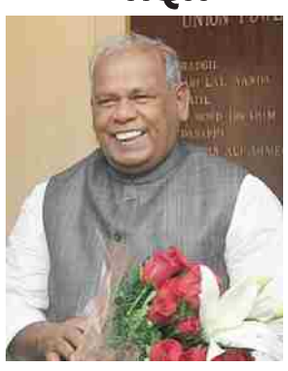

नालंदा, 14 अप्रैल (नि.सं.)। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132 वी जयंती शुक्रवार को मनाई गई। नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड के मेहंदी नगर गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी शिरकत करने पहुंचे थे।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि संसार में अगर सबसे ज्यादा किसी एक शख्स की जयंतिया मनाई जाती है तो वे बाबा भीमराव अंबेडकर हैं। संसार में सबसे ज्यादा मूर्तियां बाबा भीमराव अंबेडकर की है। इसी से समझा जा सकता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर क्या थे। अपने समय के सबसे बड़ा विद्वान, साहित्यिक, इकोनॉमिस्ट, फिलॉस्फर, और कानून विद के रूप में तो लोग जानते ही हैं। वे संविधान के रचयिता हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि संसार सहित देश और हमारे राज्य में उनकी जयंतिया मनाई जा रही है।

मीडिया के एक सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि विपक्षी एकता 2024 में जरूर सफल होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 1 साल से इसे लेकर प्रयास कर रहे थे। अब कांग्रेस का साथ मिला है तो यह जरूर मूर्त रूप लेगा। वहीं एक और सवाल पर जीतन राम मांझी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह एवं प्रधानमंत्री मोदी से इसलिए मिलने गए थे कि पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी को भारत रत्न की उपाधि मिल सके। हम कोई राजनीतिक कारणों से उनसे मिलने नहीं गए थे। वहीं नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उमीदवार पर मांझी ने कहा उन्होंने कभी भी खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं माना है। विपक्षी पार्टियां 2024 में चुनाव के बाद या चुनाव के पहले एक साथ बैठकर उम्मीदवार का चयन करेंगीं।

इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के अलावे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, एसटी आयोग के चेयरमैन शंभू कुमार सुमन, भोजपुरी सुपरस्टार कुणाल सिंह आदि लोग मौजूद रहें।

कांग्रेस ने भीमराव आंबेडकर को लोकसभा जने से रोक दिया था : नित्यानंद राय

समस्तीपुर, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि विपक्ष का कांग्रेस के साथ वैसा गठबंधन है। जो कांग्रेस बाबा साहेब भीमराव अंबेदकर को लोकसभा जाने से रोक दिया था। उसे सयम जनसंघ के पहले अध्यक्ष श्याम प्रसाद मुखर्जी ने उन्हें लोक सभा ले जाने के लिए अथक प्रयास किया था। केंद्रीय मंत्री श्री राय शुक्रवार को जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित भीम राव अंबेंदक कर जयंती समाराहे के दौरान पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।

इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित अंबेदकर जयंती समारोह को संबोधित किया है। इस मौके पर उन्होंने बाबा साहेब के चैल्य चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने बाबा साहेब अमर रहे का भी नारा लगाया। उधर पत्रकारों द्वारा नीतीश के दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मिलने को लेकर होने वाले असर के बारे में पूछे गए सवाल को वह टाल गए।

जयंती समारोह में जिले भर के कार्यकताओं ने लिया भाग लिया मौके पर रोसड़ा के भाजपा विधायक विरेंद्र कुमार , जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जगन्नाथ ठाकुर, प्रभात कुमार समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

राजद के कार्यकर्ताओं ने वाजितपुर पंचायत के रविदास टोला में भीव राव अंबेदकर की जयंती मनाई।

इस मौके पर स्थानीय राजद के विधायक सह विधानसभा में उप मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने भाग लिया।इस मौके पर उन्होंने दलितों को शिक्षित होकर संघर्ष का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा से बड़ा कोई हथरियार नहीं होता। शिक्षा का हथियार जिसके पास होता है उसे कोई भी ताकत नहीं हरा सकती।

कांग्रेस से बड़ा दलित विरोधी कोई नहीं : सुशील मोदी

पटना, 14 अप्रैल (का.सं.)। शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के नेताओं ने यह दावा किया कि समाज में जब तक गैर बराबरी रहेगा तब तक कोई आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा कभी भी आरक्षण विरोधी नहीं रही है। उन्होंने कहा कि जब देश का संविधान बना तब भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आरक्षण का समर्थन किया। इसके बाद अटल बिहार वाजपयी जी की सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी। इसके बाद 2016 में जब सर्वोच्च न्यायलय ने एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम को शिथिल करने की कोशिश की गई, तो भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही उसे री-स्टोर किया था। उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके नेता आज संविधन की रक्षा करने और आरक्षण बचाने की बात करते है। लेकिन हकीकत है कि 15 साल के शासनकाल में राजद ने किसी को आरक्षण नहीं दिया। यहां तक की पंचायत चुनाव भी बिना आरक्षण के करवाए गए थे। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी कब पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की गई।

बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब बाबा साहेब को देश का कानून मंत्री बनाया गया था। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान बंटवारे के समय योगेंद्र मंडल पाकिस्तान तो चले। लेकिन वहां उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि दो साल के बाद ही इन्हें वापस भारत आना पड़ा। उन्होंने कहा कि भारत में आज अंबेडकर जी को पूजा जाता है। जबकि पाकिस्तान में अब मंडल जी को पहचाने वाला भी नहीं है। यही पाकिस्तान और भारत में अंतर है। सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर आबादी बढ़ेगी तो आरक्षण भी बढ़ेगी, यह साफ प्रावधान है।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जब तक समाज मर गैर बराबरी है, तब तक कोई भी आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता है। उन्होंने कांग्रेस को दलित विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस प्रारंभ से ही दलित विरोधी रही है। सुशील मोदी ने कहा कि 1952 में बाबा साहेब में मुंबई से चुनाव लड़ा तक कांग्रेस ने उन्हें हराने का काम किया। कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद बाबासाहेब को भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया गया। जब भाजपा के समर्थन वाली वीपी सिंह की सरकार देश में बनी तब उन्हें सर्वोच्च सम्माान से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने तो संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगने दी। वीपी सिंह की सरकार के दौरान उनकी मूर्ति सेंट्रल हॉल में लगाई गई। उन्होंने कहा कि इन उदाहरणों से कांग्रेस की मानसिकता समझी जा सकती है। सुशील मोदी ने आरजेडी को भी दलित विरोधी बताते हुए कहा कि लालू राबड़ी के शासनकाल में हुए नरसंहार में 155 दलितों की हत्या कर दी गई और आज यही राजद बाबा साहेब की जयंती मना रही है।

धर्म बदल चुके दलितों को आरक्षण नहीं दी जाएगी : सुशील मोदी

पटना, 14 अप्रैल (का.सं.)। भारतीय जनता पार्टी ने महागठबंधन की सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस को बाबा भीम राव अंबेडकर का विरोधी बाताया है। मोदी ने शुक्रवार को कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था। वह सम्मान कांग्रेस ने नहीं दी।

बाबा साहेब अंबेडकर को बीपी सिंह की सरकार में भारत रत्न की उपाधि दी गई। कांग्रेस के प्रधानमंत्री उन्हें यह उपाधि नहीं दे सके। कांग्रेस की सरकार में भारत रत्न नहीं मिल सका। उन्होंने आगे कहा है कि संसद के सेंट्रल हाल में कांग्रेस के जमाने में बाबा साहेब का चित्र नहीं लग सका। यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। जब जनसंघ की सरकार बनी, तभी यह सम्मान मिला है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नब्बे की दशक को याद करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में क्या हुआ। राजद शासन में 15 साल में एक दर्जन सामूहिक नरसंहार हुए।दलितों को लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून दिया गया।

वही लोग आज बगल में अंबेडकर साहब की जयंती मना रहे हैं। जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी एक भी दलित का नरसंहार नहीं हुआ। राजद और कांग्रेस का चरित्र दलित विरोधी है।

पीएम मोदी की सरकार ने दलितों के लिए बने एससी-एसटी एक्ट को और कठोर किया है। बाबा साहेब के 5 स्थान को नरेंद्र मोदी ने पंचतीर्थ घोषित किया। पीएम नरेन्द्र मोदी अंबेडकर से जुड़े स्थानों को डेवलप कर रहे हैं।

सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अंबेडकर को मौका लगा तो उन्होंने ईसाई और इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। उन्हें लगा कि वे भारतीय संस्कृति से दूर चले जायेंगे। इसलिए उन्होंने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया।

जातियों और संप्रदायों से पैदा हुआ विभाजन, हमें फिर एक होने की जरूरत : मोहन भागवत

अहमदाबाद, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने विभिन्न जातियों और संप्रदायों के बीच एकता का संदेश देते हुए शुक्रवार को कहा कि पहले हम एक थे, लेकिन हमने जातियों के रूप में विभाजन पैदा किया, जिसे विदेशियों ने चौड़ा किया। इस देश के लिए हमें एक बार फिर एक बनना होगा। भागवत यहां 'समाज शक्ति संगम' कार्यक्रम में आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित संबोधित कर रहे थे।

भागवत ने डॉ. बी आर आंबेडकर को उनकी 132वीं जयंती पर याद किया और कहा कि बाबा साहेब ने कहा था कि समानता आधारित समाज से ही देश का विकास होगा। संघ प्रमुख ने कहा, 'आंबेडकर ने कहा था कि हम विदेशी आक्रमणकारियों से हार गए क्योंकि हम विभाजित थे।' उन्होंने कहा, 'पहले हम एक थे, लेकिन हमने जातियों और संप्रदायों जैसी चीजों से विभाजन पैदा किया और विदेशियों ने इसे चौड़ा कर दिया। अब देश के विकास के लिए हमें फिर से एक होने की जरूरत है।'

उन्होंने कहा, 'बड़ी चीजें एक बार हो जाने के बाद देखी जा सकती हैं लेकिन जब काम शुरू होता है तो कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता है... डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का जन्म एक ऐसी ही घटना थी। उस समय किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन हम बदलाव देख सकते हैं। डॉ. बाबासाहेब नहीं रहे लेकिन वह बदलाव आना अभी बाकी है। हमें इसकी ओर चलना होगा।'

उन्होंने आगे कहा, हमने डॉ. बाबा साहेब के नेतृत्व में अपने संविधान का मसौदा तैयार किया। जब भारत की संसद में उस संविधान का अनावरण किया गया था, तो डॉ बाबा साहेब ने दो भाषण दिए थे... यह हमारे लिए उस स्वतंत्रता के लिए खुद को योग्य बनाने के लिए एक मार्गदर्शक हैं। हमें इसे हर साल 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को पढ़ना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। वह एकता के महत्व की बात करते हैं।

अरुण सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा– उनकी तीसरी सूची नहीं आएगी

बंगलूरू, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। भाजपा के कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी करने में बहुत समय लग रहा है क्योंकि उनके नेताओं के बीच 'आंतरिक लड़ाई' चल रही है।

न्यूज एजेंसी से बात करते हुए सिंह ने कहा, उनकी तीसरी सूची नहीं आएगी, बस इंतजार कीजिए और देखते रहिए। पार्टी में नेताओं के बीच आंतरिक लड़ाई चल रही है। उम्मीदवारों के रूप में नए चेहरों को पेश करने और पुराने लोगों को छोड़ने के भाजपा के कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, हर किसी को चुनाव का टिकट नहीं मिल सकता है। स्वाभाविक रूप से, वे टिकट से वंचित होने से आहत हैं। लेकिन भाजपा के सदस्य राष्ट्र पहले की भावना के साथ एक विचारधारा के लिए काम करते हैं। पार्टी का हर सदस्य एकजुट होकर काम करेगा।

यह पूछे जाने पर कि वह किसे बेहतर दावेदार के रूप में देखते हैं, सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तीन गुटों में विभाजित है– सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और मल्लिकार्जुन खरगे। चुनावी सीटों की घोषणा होते ही कांग्रेस में घमासान मच गया।

उन्होंने कहा, भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अभी तक 212 सीटों पर 66 नए चेहरों को टिकट दिया है। भाजपा ने नए

चेहरे को मौका दिया है जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं और हमारे वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता को सम्मान भी देते हैं। पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी।

यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी के नए चेहरे बोम्मई सरकार के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी फैक्टर का मुकाबला करने में मदद करेंगे। सिंह ने कहा, कोई एंटी-इनकंबेंसी नहीं है, केवल प्रो-इनकंबेंसी है। चाहे व्यापार करने में आसानी या नवाचार का मामला होस अब कर्नाटक की स्थिति मजबूत है। कर्नाटक में बड़े पैमाने पर एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) आ रहा है। लोगों के विचार और भावनाएं भाजपा के साथ हैं।

2018 के चुनावों में भाजपा 104 सीटें जीतकर सबसे बड़ी एकल पार्टी के रूप में उभरी थी, जबकि कांग्रेस और तत्कालीन सहयोगी जद (एस) ने क्रमश: 80 और 37 सीटें जीती थीं। वर्तमान कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होगा। 224 सीटों वाली विधानसभा के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 13 मई को होगी।

एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा पहला राज्य : सीएम खट्टर

चंडीगढ़, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 14 फसलों की खरीद कर रहा है। सीएम ने कहा कि साथ ही शेष फसल की खरीदी भावांतर भरपाई योजना से की जा रही है।

सीएम ने आश्वासन दिया कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को हुए नुकसान का मई तक मुआवजा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री पलवल के होडल कस्बे में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। इस बीच सीएम ने लोगों को बैसाखी के त्योहार की भी शुभकामनाएं दीं।

सीएम खट्टर ने कहा कि सरकार आम आदमी के साथ खड़ी है और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने होडल में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को राहत देते हुए उनके लंबित वेतन का 75 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि होडल में लगभग 60 हजार की आबादी वाले 12,833 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 128 लोगों को लगभग 26 लाख रुपये का मुफ्त इलाज मिल चुका है।

इसके अलावा सीएम ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत होडल में 1160 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। पहले 5500 राशन कार्ड बनाए गए थे।

उन्होंने कहा कि सरकार अब 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए स्वत: पेंशन की व्यवस्था कर रही है जिसके अंतर्गत होडल में अब तक 44 वृद्धजनों की पेंशन की व्यवस्था की जा चुकी है। सरकार ने बुजुर्गों की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी है।

मुख्यमंत्री ने होडल मुख्य मंडी के विकास के लिए 2.5 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की। उन्होंने सड़क नेटवर्क सहित विभिन्न विकास योजनाओं को मंजूरी दी और कहा कि नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा।

'हमारे कपड़े नहीं, आपकी सोच गंदी', महुआ मोइत्रा का बीजेपी नेताओं पर तंज

नई दिल्ली, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ट्विटर के जरिए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि शुक्रवार सुबह भाजपा नेताओं और भक्तों के लिए संदेश! हम बंगाली महिलाएं हैं। हम अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनते हैं। हम अपनी मर्जी के हिसाब से ही खाते-पीते हैं। हम उसकी ही पूजा करते हैं, जिसकी आराधना हम करना चाहते हैं। हमारे कपड़े गंदे नहीं हैं। आपकी सोच गंदी है।

असल में, इस महीने की शुरुआत में एक वीडियो में कैलाश विजयवर्गीय यह कहते सुने गए थे कि महिलाएं जिन्हें देवी कहा जाता है, वे आजकल ऐसे गंदे कपड़े पहन कर निकलती हैं कि उनमें देवी का रूप दिखाई नहीं देता। वो शूर्पणखा जैसी लगती हैं। उन्होंने इसी के साथ कहा था कि युवक भी नशे की हालत में रहते हैं, जिन्हें थप्पड़ लगाने का मन करता है।

इसे लेकर कई नेता विजयवर्गीय की आलोचना कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी आपत्ति जताई थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला विंग की अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि भाजपा हमेशा से महिलाओं का सम्मान नहीं करती और इस बयान से यह साफ हो गया है।

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह से अराजकता करार दिया। महुआ ने कहा मिस्टर अजय बिष्ट जिनका दूसरा नाम 'मिस्टर ठोक दो' था। इसलिए ऐसे सज्जन व्यक्ति के अंतर्गत इस तरह की अराजकता, जंगल राज, एनकाउंटर के जरिए हत्याएं हमेशा फलती फूलती है। इसलिए ऐसा अब भी हो रहा है। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य नहीं है।

यह एक प्रकार का कल्चर या जंगल राज है। जब आपके पास ऐसे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हों जो कहें, 'गाड़ी पलट सकती है', 'ठोक दो'...तो यह कभी भी हो सकता है।

अमेरिकी संसद के प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा, पश्चिमी नौसेना कमांड के प्रमुख से की बात

नई दिल्ली, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। अमेरिकी संसद का प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर है। इस दौरान गुरुवार को प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिमी नौसेना कमांड का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने वेस्ट कमांड के कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी सहित अन्य नौसेना अधिकारियों से बात की।

विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि प्रतिनिधिमंडल को पश्चिमी नौसेना कमांड की भूमिका, जिम्मेदारी और उनके कामकाज का प्रजेंटेशन दिया गया। इस दौरान मंडल ने स्वदेशी मिसाइल गाइडेड आईएनएस मोरमुगाओ का भी दौरा किया। अमेरिकी दल ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का भी दौरा किया, जहां उन्हें स्वदेशी जहाज के निर्माण की क्षमता के बारे में बताया गया।

विज्ञप्ति में कहा है कि दोनों देशों के बीच नौसैनिक सहयोग बढ़ा है। इसमें वार्षिक अभ्यास मालाबार सहित रिमपैक, संगम, टाइगर ट्राइंफ, आईएमएक्स शामिल हैं। भारत और अमेरिका समुद्री सुरक्षा के लिए सतर्क है। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी कांग्रेस के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को दोनों देशों के सहयोग के रूप में दर्शाया है।

11304 नर्तकों और ढोल वादकों ने किया बिहू नृत्य प्रदर्शन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डस में हुआ दर्ज

गुवाहाटी, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि गुरुवार को 11,304 नर्तकों और ढोल वादकों ने एक ही स्थान पर 'बिहू' नृत्य और 'ढोल' बजाते हुए अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। बिहू लोकनृत्य का सबसे बड़ा गायन है। लंदन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मुख्यालय के एक निर्णायक टीम की मौजूदगी में कलाकारों ने अपना शो प्रस्तुत किया और 'बिहू' नृत्य और 'ढोल' के लिए वैश्विक उपलब्धि हासिल की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 'सबसे बड़ा बिहू नृत्य और सबसे बड़ा ढोल ड्रम कलाकारों की टुकड़ी' के रिकॉर्ड बनाने की उपलब्धि के लिए

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टीम से प्रमाण पत्र प्राप्त किया। 13 अप्रैल को गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में 11,304 लोक नर्तकों और 2,548 ढोल वादकों ने यह उपलब्धि हासिल की थी। गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में मेगा बिहू कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को लेजर शो कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा और अन्य नेता शामिल हुए।

केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, संजय सिंह बोले- पता था अगला नंबर केजरीवाल का है

नई दिल्ली, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने 16 अप्रैल सुबह 11 बजे बुलाया है। जानकारी सामने आ रही है कि केजरीवाल से भी दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर सवाल जवाब करेगी। अब यह बात भी सामने आ रही है कि केजरीवाल सीबीआई मुख्यालय जाएंगे और जांच में शामिल होंगे।

सीबीआई द्वारा केजरीवाल को पूछताछ के नोटिस भेजे जाने पर आम आदमी पार्टी की ओर से पहली प्रतिक्रिया देते हुए सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, अत्याचार का अंत जरूर होगा। उन्होंने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल से पहले ही कह दिया था कि जेल जाने का अगला नंबर आपका है। ये लोग (बीजेपी) मोदी जी का भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कुछ भी करेंगे और आज सीबीआई का समन आ गया।

संजय सिंह ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने देश का पैसा अपने दोस्त (अडानी) के बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगाया है। केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची गई। लेकिन इस साजिश के खिलाफ केजरीवाल की लड़ाई रुकेगी नहीं। आपने जो लाखों करोड़ों रुपये का घोटाला किया है उसके बारे में देश के हर कोने में जाकर बताना जरूरी है।

जिस केजरीवाल ने दिल्ली को स्वच्छ पानी, मुफ्त बिजली और बेहतर शिक्षा दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम थमने वाली नहीं है। आपने अपने दोस्त के साथ मिलकर लाखों करोड़ों का घोटाला किया। उसे दबाने के लिए ये गिरफ्तारी की साजिश रच रहे हैं। केजरीवाल पहले भी आपसे लड़ते रहे हैं और आगे भी आपसे लड़ते रहेंगे। आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम जारी रहेगी। ये तमाम लड़ाइयां आगे भी जारी रहेंगी। इससे ने दिल्ली वालों का काम रूका न और न वो झुके।

बता दें कि दिल्ली में नई आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हें सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

सीबीआई के नोटिस का जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी भी आक्रमक नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से इस मामले में कानूनी सलाह लेगी।

देश में कुछ ताकतें नहीं चाहतीं कि बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें : सीएम केजरीवाल

नई दिल्ली, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि देश में ऐसी ताकतें' हैं जो नहीं चाहती' कि बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें और भारत प्रगति करे। डॉ बी आर आंबेडकर की जयंती पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मुख्यालय में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा ऐसा असर पैदा कर सकती है जो गरीबी को कम करने में मदद कर सकती है।

बाद में, मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी किया जिसमें केजरीवाल ने दावा किया कि इस देश में ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहतीं कि भारत प्रगति करे। उन्होंने आरोप लगाया, वे (ये ताकतें) नहीं चाहती कि देश में बच्चे उच्च शिक्षित हों और ये वे लोग हैं जिन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने की साजिश रची।

आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख ने कहा, ऐतिहासिक रूप से भी, जब भी कोई महान व्यक्तित्व आगे आया और जनता को शिक्षित करने की कोशिश की, तो हमेशा एक निरंकुश शासक ने उस पर हमला किया।

केजरीवाल ने कहा कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अपनी शिक्षा के कारण ही इतने महान व्यक्तित्व बने। केजरीवाल ने दावा किया, हम चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चे डॉ. आंबेडकर की तरह बनें। हम मानते हैं कि प्रत्येक बच्चे में उसके जैसा बनने की क्षमता है। लेकिन ये विभाजनकारी ताकतें एक आंबेडकर को नहीं संभाल पाईं और अगर हमारे सारे बच्चे उनके जैसे हो गए तो ये ताकतें देश छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगी। इसीलिए वे हमारे बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं दे रहे हैं।

शाह पर अभिषेक बनर्जी का पलटवार, बोले- राजनीति से ले लूंगा संन्यास अगर राज्य को दें 1.15 लाख करोड़

कोलकाता, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल का दौरा किया, इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी कभी बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब इसके बाद, अभिषेक बनर्जी ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल का बकाया पैसा 1.15 लाख करोड़ रुपये जारी कर देती है, तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठ से लेकर भ्रष्टाचार तक के कई मोर्चों पर पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद उन्होंने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ट्वीट कर अमित शाह पर निशाना साधा।

ट्विटर पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्होंने मेरे बारे में काल्पनिक बातें कहीं लेकिन भाजपा ने पश्चिम बंगाल को जो नुकसान पहुंचाया है, उसे दूर करने की परवाह नहीं की।

अगर मेरा अस्तित्व आपको इस कदर परेशान करता है, तो मेरे राज्य को 1.15 लाख करोड़ रुपये का जो हक है वो दे दें। मैं खुद को राजनीतिक क्षेत्र से अलग कर लूंगा।

इससे पहले दिन में अमित शाह ने बीरभूम जिले में 'जनसंपर्क समावेश' रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ममता दीदी के इस हिटलर जैसे शासन को जारी नहीं रहने देगी। ममता बनर्जी के शासन की तुलना जर्मन तानाशाह एडॉल्फ हिटलर से करते हुए शुक्रवार को कहा कि वह सपना देख रही हैं कि उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा।

उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और जनता से 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में भारतीय जनता पार्टी को 42 में से 35 सीटें देने का आग्रह किया। उन्होंने जनता से अगले साल होने वाले आम चुनावों में भाजपा को वोट देने और 2024 में लगातार तीसरी बार पीएम बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद करने को भी कहा।

घरेलू मैदान पर पंजाब किंग्स को हराने उतरेगी लखनऊ सुपरजाइंट्स

लखनऊ (एजेंसी)। आईपीएल के 16 वें सत्र में शनिवार को लखनऊ सुपरजाइंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला होगा। इस मुकाबले में सुपरजाइंट्स को घरेलू मैदान पर खेलने का लाभ मिलेगा। सुपरजाइंट्स इस मैच में जीत के साथ ही अंकतालिका में शीर्ष पर पहुंचने उतरेगी। वहीं पिछले दो मैचों में मिली हार से उबरकर पंजाब की टीम एक बार फिर जीत की राह पर आना चाहेगी। पंजाब की टीम को शुरुआती दोनो ही मैचों में जीत मिली थी पर इसके बाद के ओवरों में बड़ा स्कोर नहीं बनाने के कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। पंजाब की मुश्किल इसलिए बढ़ी है क्योंकि कप्तान शिखर धवन के अलावा उसका कोई भी अन्य बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहा है। टीम के बल्लेबाज मध्य के ओवरों में तेजी से रन बनाने में विफल रहे हैं।

इसके अलावा टीम काफी गेंदों को खाली छोड़ रही है। पिछले मैच में ही उसने 56 गेंद खाली छोड़ी थी जिसमें टीम को सुधार करने की जरूरत है। धवन ने पहले तीन मैचों में 40, नाबाद 86 और नाबाद 99 रन की पारियां खेली थी पर टीम के अन्य बल्लेबाजों के प्रदर्शन में कमी है। युवा सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया पर इसके बाद वह भी अगले मैचों में रन नहीं बना पाये। वहीं मैथ्यू शॉर्ट और जितेश शर्मा अच्छी शुरुआत के बाद भी बड़ा स्कोर नहीं बना पाये हैं। बल्लेबाजों ने जहां पंजाब की चिन्ताएं बढ़ायी हैं। वहीं अर्शदीप सिंह , सैम कुरेन और अन्य गेंदबाजों ने अच्छा खेल दिखाया है। पिछले मैच में गेंदबाज ही गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार गेंदबाजी कर मैच को अंतिम ओवर तक ले गये थे। टीम के स्पिनरों हरप्रीत बरार और राहुल चाहर ने भी विरोधी बल्लेबाजों पर अंकुश लगाया है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ की टीम लगातार तीसरी जीत दर्ज कर अंक तालिका में नंबर एक पर पहुंचना चाहेगी।

लखनऊ की परेशानी कप्तान लोकेश राहुल को खराब फार्म है पर उसके अन्य

खिलाड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में जहां क्रुणाल पंड्या ने गेंद और बल्ले से ऑलराउंड खेल दिखाया। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ निकोलस पूरन ने 19 गेंदों पर ही 62 रन बनाकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। लखनऊ के बल्लेबाजी क्रम में सलामी बल्लेबाज काइल मायर्स के अलावा मध्यक्रम में मार्कस स्टोइनिस, पूरन और आयुष बडोनी जैसे खिलाड़ी हैं। ऑलराउंडर दीपक हुड्डा हालांकि अभी तक सफल नहीं हुए हैं। गेंदबाजी की बात करें तो टीम के पास तेज गेंदबाज मार्क वुड और आवेश खान है जबकि स्पिनर के तौर पर रवि बिश्नोई, अमित मिश्रा हैं। कुल मिलाकर देखा जाये तो लखनऊ टीम बेहद संतुलित है।

दोनो ही टीमें इस प्रकार हैं

पंजाब किंग्स: शिखर धवन (कप्तान), अर्शदीप सिंह, बलतेज सिंह, राहुल चाहर, सैम कुरेन, ऋषि धवन, नाथन एलिस, गुरनूर बराड़, हरप्रीत बराड़, हरप्रीत सिंह, विद्वाथ कावेरप्पा, लियाम लिविंगस्टोन, मोहित राठी, प्रभसिमरन सिंह, कागिसो रबाडा , भानुका राजपक्षे, एम शाहरुख खान, जितेश शर्मा, शिवम सिंह, मैथ्यू शॉर्ट, सिकंदर रजा, अथर्व तायदे।

लखनऊ सुपरजाइंट्स: केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), काइल मेयर्स, दीपक हुड्डा, कुणाल पंड्या, अमित मिश्रा, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), नवीन उल हक, आयुष बडोनी, आवेश खान, करण शर्मा, युद्धवीर चरक, यश ठाकुर, रोमारियो शेफर्ड, मार्क वुड, स्वप्निल सिंह, मनन वोहरा, डेनियल सैम्स, प्रेरक मांकड़, कृष्णप्पा गौतम, जयदेव उनादकट, मार्कस स्टोइनिस, रवि बिश्नोई, मयंक यादव।

जोकोविच को मुसेटी ने हराया, लगातार तीसरे साल मोंटेकार्लो मास्टर्स से जल्दी बाहर

मोनाको (एजेंसी)। नोवाक जोकोविच लगातार तीसरे साल मोंटेकार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट से जल्दी बाहर हो गए। एक महीने के विश्राम के बाद क्ले कोर्ट पर सत्र का अपना दूसरा मैच खेलने वाले शीर्ष रैंकिंग के जोकोविच को गुरुवार को खेले गए मैच में लोरेंजो मुसेटी ने 4-6, 7-5, 6-4 से हराया।

सर्बिया का यह खिलाड़ी अब भी क्ले कोर्ट पर सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आठ बार अपनी सर्विस गंवाई और इटली के अपने प्रतिद्वंदी के बेसलाइन के शॉट का उनके पास कोई जवाब नहीं था। जोकोविच ने मैच के बाद कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो जिस तरह का खेल मैंने आज दिखाया उससे मुझे बहुत बुरा लग रहा है।'

मोंटेकार्लो में दो बार के चैंपियन जोकोविच पिछले साल फ्रांस के कोटे डीजूर से पहले दौर में हार गए थे जबकि 2021 में और तीसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाए थे। सोलहवीं वरीयता प्राप्त मुसेटी क्वार्टर फाइनल में यानिक सिनर से भिड़ेंगे। सातवीं वरीयता प्राप्त सिनर ने दूसरे सेट में एक मैच प्वाइंट बचाकर 10वीं वरीयता प्राप्त ह्यूबर्ट हर्कज को 3-6, 7-6 (6), 6-1 से हराया।

तीसरी वरीयता प्राप्त दानिल मेदवेदेव ने भी निर्णायक टाईब्रेकर में दो मैच प्वाइंट बचाए और अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 3-6, 7-5, 7-6 (7) से हराया। मेदवेदेव दूसरी बार इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। उनका सामना अब होल्गर रूने से होगा। एक अन्य मैच में जर्मन क्वालीफायर जैन लेनार्ड स्ट्रुफ ने चौथी वरीयता प्राप्त कैस्पर रूड को 6-1, 7-6 (6) से उलटफेर का शिकार बनाया। स्ट्रुफ का अगला मुकाबला 2021 के उपविजेता आंद्रे रुबलेव से होगा, जिन्होंने करेन खाचानोव को 7-6 (4), 6-2 से हराया। दो बार के गत चैंपियन स्टेफानोस सितसिपास ने निकोलस जैरी को 6-3, 6-4 से शिकस्त दी।

हमीरपुर में खेलों के आयोजन की अच्छी संभावनाएं : ठाकुर

हमीरपुर (एजेंसी)। हिमाचल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर में खेलों के आयोजन की अच्छी संभावनाएं हैं। इसी को देखते हुए इस जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) में खेल सुविधाओं को और बढ़ाया जा रहा है। ठाकुर ने यहां साइ के एनसीओई में बैडमिंटन कोर्ट, मैट हॉल, जूडो हॉल और मुक्केबाजी हॉल का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। ठाकुर ने कहा कि उत्कृष्टता केंद्र में आधुनिक सुविधाएं होने पर खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण की सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि उत्कृष्टता केंद्र का विस्तार किया जाएगा और यदि जमीन उपलब्ध होती है तो यहां कम से कम 20 खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं तथा छात्रावास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने युवाओं से इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए खेलों के क्षेत्र में आगे आने को कहा।

ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया पहल के तहत अगले पांच वर्षों में खेल सुविधाओं पर ही करीब 3200 करोड़ रुपए खर्च कर इनका विकास किया जाएगा जिससे युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया पहल के तहत भारत में अगले पांच साल में खेल सुविधाओं पर करीब 3200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार हर राज्य में खेल सुविधाओं पर काम करेगी। ठाकुर ने सिंथेटिक ट्रैक एवं अन्य खेल सुविधाओं को लेकर कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय उद्यमियों, स्वयंसेवकों, खेल प्रेमियों और समाज के प्रमुख लोगों को आगे आना चाहिए।

फैंस के बीच डब्ल्यूपीएल की भी बढ़ेगी लोकप्रियता, बीसीसीआई ने आईपीएल की तरह तैयार किया खास प्लान

मुम्बई (एजेंसी)। महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) अगले संस्करण से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की तरह 'होम-अवे' प्रारूप में बड़ी 'विंडो' के साथ संभवतः फरवरी में खेली जाएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) में एक सूत्र ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। टूर्नामेंट का शुरुआती चरण मुंबई में दो स्थलों में चार से 26 मार्च तक खेला गया था। इस महीने के शुरु में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) चेयरमैन अरुण धूमल ने पीटीआई को बताया था कि डब्ल्यूपीएल अगले तीन सत्र के लिए पांच टीमों का टूर्नामेंट रहेगा और यह 'होम एंड अवे' (घरेलू और प्रतिद्वंद्वी टीम के मैदान) प्रारूप में खेला जायेगा क्योंकि प्रशंसक बनाने के लिए यह अहम होता है।

बीसीसीआई के सूत्र ने हालांकि कहा कि लीग को टीयर-2 शहरों जैसे इंदौर में ले जाना मुश्किल होगा क्योंकि इनके नाम पर डब्ल्यूपीएल फ्रेंचाइजी नहीं है। सूत्र ने कहा कि चर्चा यह भी चल रही है कि डब्ल्यूपीएल को साल के अंत तक स्थगित कर दिया जाये ताकि इसे दिवाली के समय आयोजित किया जाये लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। वहीं भारत-पाकिस्तान के विश्व कप स्थल और एशिया कप स्थल पर चर्चा अब भी जारी है। बीसीसीआई एशिया कप 2023 में भागीदारी को लेकर और विश्व कप के दौरान पाकिस्तान के भारत में मैचों पर भारत सरकार के निर्देशों का इंतजार करेगा।

सूत्र के अनुसार सभी सदस्य इस मामले पर

चर्चा कर रहे हैं और अंतिम फैसला इसके बाद ही लिया जायेगा। पीटीआई ने पहले बताया था कि पाकिस्तान के ज्यादातर विश्व कप मैच चेन्नई और कोलकाता में हो सकते हैं क्योंकि टीम अपने पिछले दौरों पर इन दो स्थलों पर सुरक्षित महसूस कर रही थी। बीसीसीआई को उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मुख्य चयनकर्ता की नियुक्ति अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे श्रृंखला से पहले कर ली जायेगी जिसके जून में ओवल में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के बाद होने की उम्मीद है। यह पद इस साल फरवरी में चेतन शर्मा के इस्तीफे के बाद से खाली पड़ा है।

बीसीसीआई को साथ ही भरोसा है कि भारत के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह विश्व कप 2023 के लिए फिट होंगे जो पीठ की चोट के कारण क्रिकेट से बाहर हैं। भारत साल के अंत में अक्टूबर-नवंबर में 50 ओवर के टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा और इसके कार्यक्रम के जल्द ही आने की उम्मीद है। सूत्र ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि बोर्ड भारत के सक्रिय खिलाड़ियों को दुनिया भर में विभिन्न टी20 लीगों में हिस्सा नहीं लेने देने की नीति जारी रखेगा।

डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ नहीं मिले यौन उत्पीड़न के सबूत : रिपोर्ट

नई दिल्ली । भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे धमकी देने और यौन शोषण के मामले में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के संकेत एक रिपोर्ट से मिले हैं। बृजभूषण पर कई पहलवानों ने शोषण के आरोप लगाये थे। उनके खिलाफ आरोप लगाने वाले पहलवानों में विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक भी शामिल थे। इन पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के प्रमुख के खिलाफ कई आरोप लगाने के साथ ही जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। पहलवानों ने कहा था कि महासंघ को भंग कर बृजभूषण को अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। इसी के बाद खेल मंत्रालय ने महान मुक्केबाज एमसी मेरीकोम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया था और उसे एक महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा था। बाद में सह समय सीमा दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दी गई और प्रदर्शनकारी पहलवानों की मांग पर बबीता फोगाट को जांच पैनल में छठे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। समिति ने अप्रैल के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंप पर खेल मंत्रालय ने अभी इसे सार्वजनिक नहीं किया है पर एक रिपोर्ट के अनुसार महासंघ प्रमुख के खिलाफ अब तक कोई बड़ा सबूत नहीं मिला है। इसमें कहा गया है कि डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को पहलवान साबित नहीं कर सके हैं।

अगले एक दशक में विश्व क्रिकेट पर रहेगा शुभमन गिल का दबदबा : हेडन

नयी दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज मैथ्यू हेडन का मानना है कि बड़े स्कोर बनाने की अपनी काबिलियत के कारण शुभमन गिल का अगले एक दशक में विश्व क्रिकेट में दबदबा रहेगा। तेईस वर्षीय गिल अभी तक टेस्ट मैचों में दो, वनडे में चार और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक शतक लगा चुके हैं। उनकी 49 गेंदों पर खेली गई 67 रन की शानदार पारी से गुजरात टाइटंस ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स को छह विकेट से हराया। हेडन उन कई लोगों में शामिल हैं जो गिल के खेल पर नियंत्रण बनाए रखने के कौशल से प्रभावित हैं। हेडन ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, '' गुजरात टाइटंस को पंजाब किंग्स के अच्छे गेंदबाजी आक्रमण के सामने लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो जिम्मेदारी संभालकर आखिर तक टिका रहे और शुभमन गिल ने यह भूमिका अच्छी तरह से निभाई।'' उन्होंने कहा, '' उसके कुछ शॉट ने आंखों को सुकून पहुंचाया। वह इतना अच्छा खिलाड़ी है के अगले एक दशक में विश्व क्रिकेट में उसका दबदबा रहने वाला है।

दोहा डाइमंड लीग में स्वर्ण जीतने के इरादे से उतरेंगे नीरज , पीटर्स और वाडलेच

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अगले माह दोहा में पांच मई को होने वाली डाइमंड लीग प्रतियोगिता के साथ ही नये सत्र की शुरुआत करेंगे। नीरज ने गत वर्ष भी सितंबर में डाइमंड लीग का खिताब जीता था। नीरज के अलावा अलावा विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स और ओलंपिक रजत पदक विजेता याकुब वाडलेच भी 14 चरण की इस सत्र की इस पहली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। पिछले साल स्टॉकहोम में डाइमंड लीग प्रतियोगिता में रजत पदक की जीत के दौरान 89.94 मीटर भाला फेंककर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चोपड़ा अभी तुर्की में अभ्यास कर रहे हैं। वह अभ्यास के लिए 31 मई तक वहीं रहेंगे।

नीरज चोटिल होने के कारण ही दोहा 2022 डाइमंड लीग में भी शामिल नहीं हुए थे। वहीं एंडरसन ने 93.07 मीटर की दूरी के साथ खिताब जीता था जो इतिहास की पांचवीं सबसे लंबी दूरी थी। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता वाडलेच 90.88 मीटर के निजी सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ तब दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तिकड़ी के अलावा दोहा प्रतियोगिता में यूरोपीय चैंपियन जर्मनी के जूलियन वेबर, त्रिनिदाद एवं टोबैगो के पूर्व ओलंपिक चैंपियन केशोर्न वालकोट, पूर्व विश्व चैंपियन और 2016 ओलंपिक रजत पदक विजेता कीनिया के जूलियस येगो भी भाग लेंगे। चोपड़ा की नजरें यहां जीत के साथ ही इस साल 90 मीटर के लक्ष्य को हासिल करने पर टिकी हैं। चोपड़ा ने कहा, ''मैं 90 मीटर की दूरी के करीब पहुंच रहा हूं इसलिए इसे हासिल करना मेरे लिए काफी मायने रखता है।'' उन्होंने कहा, ''पिछला साल मेरे लिए अच्छा था जहां विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ मैंने निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और वांडा डाइमंड लीग जीती। यह साल नए मौके लेकर आएगा। इन गर्मियों में मेरा लक्ष्य विश्व चैंपियनशिप के साथ एशियाई खेल हैं और वांडा डाइमंड लीग खिताब का बचाव भी करना है।''

अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता

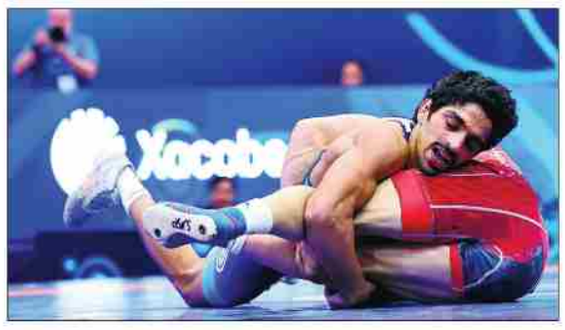

नई दिल्ली। अमन सहरावत ने सीनियर स्तर पर प्रभावी प्रदर्शन जारी रखते हुए गुरुवार को यहां 57 किग्रा वर्ग में किर्गिस्तान के अल्माज समानबेकोव को हराकर भारत को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। सहरावत ने फाइनल में समानबेकोव को 9-4 से शिकस्त दी। दिल्ली के प्रतिष्ठित छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करने वाले सहरावत ने क्वार्टर फाइनल में जापान के रिकुतो अराई को 7-1 से हराने के बाद सेमीफाइनल में चीन के वानहाओ झू को 7-4 से शिकस्त दी। पिछले साल अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले सहरावत ने 2023 सत्र में दूसरा पोडियम स्थान हासिल किया। उन्होंने फरवरी में जागरेब ओपन में भी कांस्य पदक जीता था। दो अन्य भारतीय पहलवान भी गुरुवार को कांस्य पदक के मुकाबले में जगह बनाने में सफल रहे। दीपक कुकना (79 किग्रा) और दीपक नेहरा (97 किग्रा) अपने सेमीफाइनल मुकाबले हारने के बाद कांस्य पदक के मुकाबले में खेलेंगे। अनुज कुमार (65 किग्रा) और मुलायम यादव (70 किग्रा) पदक दौर में जगह बनाने में नाकाम रहे। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 12 पदक जीते हैं। ग्रीको रोमन पहलवानों ने चार पदक जीते जबकि महिला पहलवानों ने सात पदक अपने नाम किए।

आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की जंग में ये खिलाड़ी है शामिल, यहां जाने कौन बनेगा दावेदार

चेन्नई (एजेंसी)। इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक रन बनाने और सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को टूर्नामेंट के अंत में खास खिताब मिलता है। इस बार आईपीएल के मुकाबले बेहद दमदार होते जा रहे है। आईपीएल में हमेशा ही दोनों कैप को लेकर कासी रोचक जंग देखने को मिलती है।

ये है ऑरेंज कैप के दावेदार

इस बार ऑरेंज कैप के लिए कई खिलाड़ी दावेदार है। इसमें सबसे ऊपर शिखर धवन का नाम है। शिखर धवन ने चार पारियों के खेलते हुए दो बार नॉट आउट रहकर सबसे अधिक 233 रन बनाए है। अपनी पारियों में वो दो अर्धशतक जड़ चुके है। आईपीएल में सबसे अधिक रन 99 नॉटआउट भी शिखर धवन ने ही बनाने है। इस खिताब को पाने के लिए शिखर को डेविड वार्नर (209) और जोस बटलर (204) से भी कड़ी चुनौती मिल रही है। ऋतुराज गायकवाड़ (197) और शुभमन गिल (183) भी ऑरेंज कैप के लिए दावेदारी ठोक सकते है।

ये है पर्पल कैप के दावेदार

आईपीएल में ऑरेंज कैप के बाद पर्पल कैप दी जाती है जो की सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को मिलती है। इस समयनीस लिस्ट में युजवेंद्र चहल का नाम सबमसे ऊपर है। चहल अब तक 10 विकेट चटका चुके है। पर्पल कैप की लिस्ट में राशिद खान और मार्क वुड भी शामिल है।

यूरोपा लीग : मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सेविला से 2-2 से ड्रॉ खेला

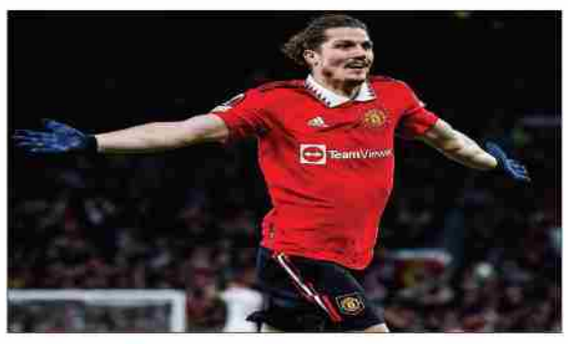

मैनचेस्टर। मार्सेल सेबिजर के पहले हाफ में किए गए दो गोल की मदद से मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोपा लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाने की तरफ मजबूती से कदम आगे बढ़ा रहा था लेकिन अंतिम क्षणों की चूक के कारण उसे सेविला से क्वार्टर फाइनल के पहले चरण का मैच 2-2 से ड्रॉ खेलना पड़ा। सेबिजर ने 14वें और 21वें मिनट में गोल करके मैनचेस्टर यूनाइटेड मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था लेकिन टाइरेल मलासिया ने 84वें मिनट में आत्मघाती गोल कर दिया। इसके बाद हैरी मैग्वायर ने इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में बराबरी का गोल दागा। क्वार्टर फाइनल का दूसरा चरण अगले सप्ताह स्पेन में खेला जाएगा। इस बीच मैट्स वीफर के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से फेयेनोर्ड ने यूरोपा लीग के पहले चरण के क्वार्टर फाइनल मैच में रोमा को 1-0 से हराया। युवेंटस ने क्वार्टर फाइनल चरण के पहले मैच में डिफेंडर फेडेरिको गट्टी के 73वें मिनट में किए गए गोल से स्पोर्टिंग लिस्बन को 1-0 से पराजित किया।

रूस और बेलारूस के साथ नहीं खेंलेगे यूक्रेन के एथलीट, सरकार ने लगाया प्रतिबंध

मॉस्को (एजेंसी)। यूक्रेन सरकार ने अपने एथलीटों पर रूस और बेलारूस के एथलीटों के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकृत सूत्रों के अनुसार यूक्रेन के युवा और खेल मंत्रालय ने यूक्रेनी एथलीटों को रूसी और बेलारूसी एथलीटों के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। खेल मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित हुए इस फरमान पर उप खेल मंत्री मत्ली बिदनी के हस्ताक्षर हैं।

मंत्रालय के अपने फरमान में लिखा कि यूक्रेन की राष्ट्रीय टीमों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों को अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा रहा है, जिसमें रूस और बेलारूस के एथलीट भाग ले रहे हैं। यूक्रेनी मंत्री और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य ओलेह नेमचिनोव ने मार्च के आखिरी सप्ताह में कहा था कि यूक्रेन सरकार ने अपने एथलीटों को 2024 ओलंपिक के लिए क्वालीफाइंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का फैसला किया है, क्योंकि इस प्रतियोगिताओं में रूसी एथलीट भी हिस्सा लेंगे।

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने कहा कि यूक्रेन के एथलीटों को रूसियों के साथ टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने से रोकने के कीव के फैसले से केवल यूक्रेनी खेलों को नुकसान होगा और यह यूक्रेनी एथलीटों की मनोदशा पर असरकारक होगा। ओलंपियन कंकाल रेसर व्लादिस्लाव हेरास्केविच सहित कुछ यूक्रेनी एथलीटों ने प्रतिबंध की आलोचना करते हुए कहा कि इससे यूक्रेनी खेलों पर बेहद बुरा असर पड़ेगा।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अगर यूक्रेनी प्रतिनिधि प्रतियोगिताओं में उपस्थित नहीं होते हैं, तो हम अंतरराष्ट्रीय खेल मैदानों को पूरी तरह से खाली कर देते हैं और रूसी/बेलारूसी प्रतिनिधियों को उनके आख्यानों और प्रचार को बढ़ावा देने का अवसर देते हैं। मंत्रालय ने निर्देश दिया कि उनके आदेश का अनुपालन किया जाए। मंत्रालय के आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में यूक्रेन के खेल संघ राष्ट्रीय महासंघ के दर्जे से वंचित हो जाएंगे। आदेश में रूसी और बेलारूसी एथलीटों के भाग लेने पर टूर्नामेंट से यूक्रेनी एथलीटों के प्रतिनिधिमंडल को वापस बुलाने का भी प्रावधान है।

गौरतलब है कि आईओसी के प्रमुख

थॉमस बाक ने 28 मार्च को कहा था कि आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय खेल संघों की सिफारिश की थी कि रूसी और बेलारूसी एथलीटों को तटस्थ ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाए, लेकिन अगर वे यूक्रेन में चल रहे सैन्य अभियान का समर्थन करते हैं तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं होगी।

एनएसए जैसे दमनकारी 'काले कानूनों' को रद्द करें : सुखबीर बादल

चंडीगढ़, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) जैसे सभी लोकतांत्रिक और दमनकारी काले कानूनों को रद्द करने की मांग की और पंजाब में आप सरकार द्वारा उनके बड़े पैमाने पर गलत दुरुपयोग को रोकने का आह्वान किया। बादल ने कहा, यह पंजाबियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सत्तारूढ़ पार्टी की अक्षमता और विफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाने का एक प्रयास है।

अकाली दल प्रमुख ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसमें अनुभव और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देश की छवि पर उनके प्रतिकूल प्रभाव के आलोक में इन काले कानूनों को निरस्त करने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की।

बादल ने कहा कि आप सरकार ने इन दमनकारी कानूनों को खालसा पंथ के सदस्यों, खासकर निर्दोष सिख युवाओं के खिलाफ हथियार में बदल दिया है। यहां तक कि बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों सहित सिख परिवारों के निर्दोष सदस्यों को भी दमन का शिकार होना पड़ रहा है।

निर्दोष और देशभक्त सिख समुदाय के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना करते हुए, बादल ने कहा कि सरकार सिख युवाओं को केवल संदेह के आधार पर उठा रही है और उन्हें दमनकारी कानूनों के तहत गिरफ्तार कर रही है और उन्हें डिब्रूगढ़ जैसे दूर स्थानों पर भेज रही है।

ऐसे कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग करते हुए राज्य के पूर्व गृह मंत्री बादल ने कहा कि लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं सहित राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इस तरह के कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ती सियासत

भोपाल, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में भले ही छह महीने से ज्यादा का वक्त हो मगर सियासत की राह तय होने लगी है और धीरे-धीरे वह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ भी बढ़ रही है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा मुस्लिम समाज की आबादी कम होने का जिक्र किया गया और उस पर भाजपा हमलावर हो गई।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि, भाजपा और संघ जो प्रचार करती है कि देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है वो सरासर झूठ, गलत और अप्रमाणित है, क्योंकि हिंदुओं की तुलना में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या तेजी से घट रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जनगणना को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने जनगणना कराए जाने पर जोर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर भाजपा हमलावर हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि चाहे कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह एक वर्ग को डराने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मुस्लिमों की संख्या घट रही और कमलनाथ ने रोजा इफ्तार में कहा दंगे भड़क रहे हैं। मध्य प्रदेश शांति वाला राज्य है। चुनाव के समय कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं दंगे भड़क रहे हैं, दूसरे नेता कह रहे संख्या घट रही है, क्यों डराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके इरादे क्या है। मुझे अजीब लगता है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की चर्चाएं हो रही है जो सर्वथा शांति प्रदेश है और शांति का टापू है।

सियासी तौर पर आ रहे बयानों ने यह तो जाहिर कर ही दिया है कि राज्य की सियासत ध्रुवीकरण की तरफ तेजी से बढ़ रही है।

भारत-नेपाल सीमा पर दोनों देशों के नागरिकों ने मनाया नए साल का जश्न

अनुगामिनी का.सं.

गेजिंग, 14 अप्रैल । नेपाली नववर्ष 2080 के अवसर पर आज सिक्किम में भारत-नेपाल सीमावर्ती चिउवा भंज्यांग में दोनों देशों के नागरिकों भारी संख्या में उपस्थित होकर मैत्रीपूर्ण सम्बंध बनाए रखते हुए नए साल का जश्न मनाया। भीड-भाड़ से परे अपने भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य तथा हाल ही में नई सड़क खुल जाने के बाद से सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 161 किमी. और दार्जिलिंग से 99 किमी. दूर यह अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र चिउवा भंज्यांग राज्य के पर्यटन मानचित्र में तेजी से प्रसिद्ध हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा होने के कारण यहां दोनों देशों के सुरक्षाकर्मी तैनात भी रहते हैं।

आज नेपाली नव वर्ष पर भारत और नेपाल के हजारों की संख्या में नागरिक अपने वाहनों के साथ चिउवा भंज्यांग पहुंये थे। जो स्थान पहले मवेशियों के लिए चारागाह था, आज वह पर्यटकों का पसंदीदा स्थान बन गया है। इसके कारण सिक्किम के पर्यटन व्यवसाय को एक नया आयाम मिला है। चिउवा भंज्यांग पश्चिम सिक्किम में देशी-विदेशी पर्यटकों का दिल जीतने वाले याकसोम, पेलिंग, उत्तरे, बरशे आदि पर्यटन स्थलों में शुमार हैं, जो अपने विशिष्ट प्राकृतिक अवस्थिति एवं सौन्दर्य के कारण सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। उत्तरे जहां 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, वहीं चिउवा भंज्यांग 11500 किमी. की ऊंचाई पर अवस्थित है। यहां से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ का विहंगम दृश्य बरबस ही लोगों को मुग्ध कर देता है। इसके पूर्व में जमले चंगा-जिसमें चेंज फॉल्स और पेलिंग शामिल हैं-स्थित है। वहीं पश्चिम में फोकटेडांड़ा, उत्तर में नेधम एवं बरशे सहित नेपाल का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। वहीं इसके दक्षिण में दार्जिलिंग का संदकफू स्थित है।

बागडोगरा हवाई अड्डा से होते हुए सिक्किम के प्रवेश द्वार मल्ली, जोरथांग, सोरेंग, कालुक देंताम, सिंगसर ब्रिज होते हुए यह स्थान 164 किमी. दूर है। अकेले उत्तरे से ही पर्यटकों के लिए इन सभी पर्यटन स्थलों तक पहुँचने के लिए कई मार्ग हैं।

एडवेंचर पर्यटन के दृष्टिकोण से पर्यटक दार्जिलिंग सीमा बरशे रोडोडेंड्रोन सेंचुरी से शुरू कर गोरखे, फालुत, तोरीफुले, सिंगलिला, जरीबुटे, अचले, थुलो धाप, कालीझार, फोकते डांड़ा, चिउवा भंज्यांग, मेजर थम होते हुए भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र मेगु, पांगमेलुंग, लाम पोखरी, दानफे भीर, टिमबुंग पोखरी, हंस पोखरी, लंपोखरी, जामले पोखरी, नीर पोखरी, मयूर पोखरी, गोमाथांग, तिगेप्ला, खंगरदीन, यांगसेप, पांगडिंग, दुध पोखरी, बिखबारी, जांगरी, थांगसिंग, समिति, लामुने, जेमाथांग, गोचला से होते हुए योकसाम तक 15 दिनों की पैदल यात्रा करते हैं। इस दौरान पर्यटक जंगल और जंगली जानवरों, जड़ी-बूटियों, पहाड़ों, झीलों, बर्फ से ढंकी चोटियों और भौगोलिक क्षेत्रों का आनंद उठाते हैं। वहीं 2007 से दोनों देशों के नागरिक पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु कार्यरत हैं।

ऐसे में यह कहा जा सकता है कि यदि सिक्किम सरकार इस क्षेत्र के पर्यटन पर ध्यान देती है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि सिक्किम के ये सभी स्थान बेहतरीन पर्यटन गंतव्य बन सकते हैं। साथ ही यहां के ट्रैकिंग रूटों और स्थलों की पहचान कर इसे और विकसित किया जा सकता है।

दया याचिका में अत्यधिक देरी से मौत की सजा का उद्देश्य हो जाएगा विफल : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दया याचिका पर फैसला करने में अत्यधिक देरी से मौत की सजा का उद्देश्य विफल हो जाएगा। इसलिए राज्यों व सक्षम अधिकारियों द्वारा दया याचिका पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए।

जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. रविकुमार ने कहा कि यह सच है कि मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के दौरान अपराध की गंभीरता एक प्रासंगिक विचार हो सकता है, लेकिन दया याचिकाओं के निपटान में अत्यधिक देरी को भी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलते समय एक प्रासंगिक विचार कहा जा सकता है।

अगर अंतिम निष्कर्ष के बाद भी दया याचिका पर फैसला करने में अत्यधिक देरी होती है, तो मौत की सजा का उद्देश्य और उद्देश्य विफल हो जाएगा। इसलिए राज्य सरकारों /या संबंधित अधिकारियों को दया याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, ताकि दोषी को को भी अपने भाग्य का पता चल सके और पीड़ित को भी न्याय मिल सके।

पीठ ने कहा कि जगदीश बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2020) में, पांच साल से अधिक समय से लंबित दया याचिका के निपटान में देरी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का निर्देश दिया, और इस आधार पर मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के अन्य फैसलों का भी हवाला दिया।

शीर्ष अदालत का आदेश बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर आया। उच्च न्यायालय ने 1990 से 1096 के बीच कोल्हापुर जिले में 13 बच्चों के अपहरण व उनमें से नौ की हत्या की दोषी रेणुका और उसकी बहन को दी गई मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को इस आधार पर आजीवन कारावास में बदल दिया है कि दया याचिकाओं पर फैसला नहीं करने में राज्य/राज्य के राज्यपाल की ओर से अत्यधिक अस्पष्ट देरी हुई है। दोषियों की दया याचिका को लगभग 7 साल 10 महीने तक लंबित रखा गया।

उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा, उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के फैसले और आदेश को संशोधित किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि दोषियों को प्राकृतिक जीवन के लिए और बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की सजा काटनी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा, हम उन सभी राज्यों/उपयुक्त अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि जिनके समक्ष दया याचिकाएं दायर की जानी हैं और/या जिन्हें मौत की सजा के खिलाफ दया याचिकाओं पर फैसला करना आवश्यक है, ऐसी दया याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला करें। दया याचिकाओं पर फैसला न करने में देरी का लाभ दोषियों को नहीं मिलता है।

बीजेपी ने दी बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 14 अप्रैल । भारतीय जनता पार्टी की सिक्किम अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आज 132वीं अम्बेडकर जयंती पर सिंगताम स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डीआर थापा, विधायक दल के नेता एनके नरेंद्र कुमार सुब्बा, उपाध्यक्ष अर्जुन राई, महासचिव भरत दुलाल एवं अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष बीरेन्द्र पौराली के अलावा अन्य पदाधिकारी, प्रदेश, जिला एवं मंडल कार्यकारिणी के लोग उपस्थित रहे।

दीप प्रज्वलन और डॉ. बीआर अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद बीरेंद्र पौराली द्वारा बाबा साहेब की जीवनी पर वक्तव्य के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उन्होंने सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में बाबा साहेब के योगदान, एक समावेशी भारतीय संविधान के प्रारूपण के साथ ही उनके संघर्षों पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा एससी समुदाय के उत्थान के लिए शुरू की गई प्रमुख योजनाओं और उनसे सम्बंधित पंचतीर्थ विकसित करके बाबासाहेब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने के प्रयासों के बारे में भी बताया।

वहीं सभा को सम्बोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डीआर थापा ने बाबा साहेब की जीवन शैली का हवाला देकर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए विभिन्न संगठनात्मक और सिक्किम के वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर विचार रखा।

कार्यक्रम के बाद संगठनात्मक समन्वय बैठक हुई जिसमें जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत करने हेतु आगामी गतिविधियों और रणनीतियों पर चर्चा की गई। बैठक में विधायक दल के नेता एनके सुब्बा, उपाध्यक्ष अर्जुन राई और महासचिव भरत दुलाल ने विभिन्न संगठनात्मक मुद्दों और आगामी गतिविधियों पर मार्गदर्शन किया। वहीं इस दौरान 2023-26 के लिए पार्टी के पांच जिलाध्यक्षों को भी नियुक्ति किया गया। इनमें गेजिंग जिले के लिए दिगुम लिंबू, सोरेंग जिले के लिए बाईचुंग राई, नामची के लिए सीएल गुरूंग, पाकिम जिले के लिए दिलीप राज प्रधान और मंगन के लिए ताशी ओंगडुप लेख्रचा शामिल रहें। प्रदेश अध्यक्ष ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को नियुक्ति पत्र सौंपे।

भारतीयों को बांटने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने वाले 'असली राष्ट्र विरोधी' : सोनिया गांधी

नई दिल्ली, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर की जयंती पर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि सत्ता का दुरुपयोग और संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है।

सोनिया गांधी ने यह दावा भी किया कि भारतीय नागरिकों को धर्म, जाति, भाषा और लिंग के आधार पर बांटने एवं उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने वाले असली राष्ट्र विरोधी हैं।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने लोगों का आह्वान किया कि वे सुनियोजित ढंग से हो रहे हमले से संविधान को बचाने के लिए कदम बढ़ाएं।

आंबेडकर जयंती पर समाचार पत्र द टेलीग्राफ में लिखे एक लेख में सोनिया गांधी ने कहा, आज हम बाबासाहेब की विरासत का सम्मान करते हैं। इसके साथ ही हमें उनकी उस चेतावनी को भी याद रखना होगा कि संविधान की सफलता उन लोगों के व्यवहार पर निर्भर करती है जिन्हें शासन करने का उत्तरदायित्व मिला है।

उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार सत्ता का दुरुपयोग, संविधान को नष्ट कर रही है तथा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की बुनियादों को कमजोर कर रही है।

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख ने यह आरोप भी लगाया कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय उन्हें प्रताड़ित करने के लिए सत्ता दुरुपयोग किया जा रहा जिससे स्वतंत्रता को खतरा पैदा हुआ है तथा चुनिंदा मित्रों को फायदा पहुंचाने वाले व्यवहार से समता की बुनियाद को आघात लगा है।

उन्होंने दावा किया कि भारतीय नागरिकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और नफरत का माहौल पैदा करने से बंधुता का भी क्षरण हुआ है तथा सतत अभियान के जरिये न्यायपालिका पर दबाव बनाकर अन्याय बढ़ाया जा रहा है।

सोनिया गांधी ने कहा, अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर आंबेडकर ने जाति व्यवस्था को बंधुता की बुनियाद पर हमला बताया था और इसे राष्ट्र विरोधी करार दिया था।

उन्होंने आरोप लगाया, आज असली राष्ट्र विरोधी वह लोग हैं जो भारतीय नागरिकों को धर्म, जाति, भाषा और लिंग के आधार पर बांटने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं।

सोनिया गांधी ने कहा, शुक्र है कि सत्ता के प्रयासों के बावजूद भारतीय नागरिकों में बंधुता की भावना की जड़ें गहरी हैं।

शिवराज ने की घोषणा- महेश्वर में बनेगा देवी अहिल्या बाई लोक, करही बनेगी तहसील

भोपाल, 14 अप्रैल (एजेन्सी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महेश्वर में कई सौगातें दी। उन्होंने उज्जैन के श्री महाकाल महालोक की तर्ज पर महेश्वर में पुण्य श्लोक देवी अहिल्या लोक बनाने की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि करही को तहसील बनाया जाएगा और बलवाड़ा को तहसील टप्पा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शुक्रवार को महेश्वर में डॉ. बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की जयंती और महिला महासम्मेलन को संबोधित किया।

राज्यपाल पटेल ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनके बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ के संकल्प से निरंतर बहन-बेटियां सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। मैंने मध्यप्रदेश के सभी 52 जिले घूमे हैं। मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में जनता की खुशहाली के लिए हर जगह अद्भुत कार्य हो रहे हैं, जिन्हें मैं गिना नहीं सकता। इस अवसर पर 12 करोड़ 19 लाख 18 हजार रुपये के अधो-संरचना विकास कार्य- मातमूर और 10 करोड़ की लागत वाले 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डलेश्वर का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन कार्य का शिलान्यास किया। विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितलाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री चौहान ने महेश्वर तहसील के करही टप्पा को तहसील बनाने, बलवाड़ा और कालकूट को टप्पा का दर्जा देने, कटरगांव उप स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अपग्रेडेशन और कसरावद-पिपलगोंद मार्ग निर्माण की घोषणा की। कार्यक्रम का शुभारंभ बेटियों के पूजन से हुआ। कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, जनजाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, जन-प्रतिनिधि, अधिकारी, बड़ी संख्या में बहनें और जन-सामान्य उपस्थित थे। स्वागत भाषण सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने दिया।

शिवराज ने कहा कि महेश्वर का गौरवशाली इतिहास रहा है। मां अहिल्या बाई होलकर ने विभिन्न मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। मानव सेवा के उत्कृष्ट कार्य किए। चौहान ने घोषणा की कि महेश्वर के गौरवशाली इतिहास और मां अहिल्या के कार्यों को रेखांकित करते हुए मां देवी अहिल्या बाई लोक बनाया जाएगा। ताकि उनके आदर्शों, कार्यों को लोग जाने और अनुकरण कर सकें।

शिवराज ने कहा कि प्रदेश में बहन, बेटियों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई, जिसके माध्यम से बेटियों को समय-समय पर शिक्षा के लिए राशि और 21 वर्ष की आयु होने पर एक लाख रुपये की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सरकार गरीब बेटियों की शादी करवाती है। संबल योजना में 16 हजार रुपये प्रसूति सहायता दी जाती है। बहनों के सशक्तिकरण के लिए पंचायत एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में 50 प्रतिशत आरक्षण है। बहनों को पुलिस की भर्ती में 30 प्रतिशत और शिक्षकों की भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। जमीन, जायदाद की रजिस्ट्री बहनों के नाम कराने पर केवल 1 प्रतिशत स्टांप शुल्क लिया जाता है। बहनों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लाड़ली बहना योजना प्रारंभ की गई है। योजना में गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार की बहनों को प्रतिमाह 1000 रूपये की सहायता आगामी 10 जून से मिलना प्रारंभ हो जाएगी।

डियर साप्ताहिक लॉटरी
खड़गपुर निवासी ने
₹ 1 करोड़ जीते

खड़गपुर, पश्चिम बंगाल के श्री दीपक कुमार सिंह ने **12.03.2023** को सम्पन्न हुए डियर साप्ताहिक लॉटरी के ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार के तौर पर रु. 1 करोड़ जीते हैं। उनकी विजेता टिकट का नंबर **96H 35965** है। उन्होंने कोलकाता स्थित नागालैंड स्टेट लॉटरीज के नोडल अधिकारी के पास प्राइज क्लेम फॉर्म के साथ अपनी पुरस्कार-विजेता टिकट जमा कर दी है। ''डियर लॉटरी से पुरस्कार राशि के एक करोड़ रुपए जीतने के बाद मुझे बेहद खुशी महसूस हुई। इस बेहतरीन अवसर के लिए मैं डियर लॉटरी तथा नागालैंड स्टेट लॉटरीज को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस विशाल पुरस्कार राशि के साथ मेरी सारी आर्थिक चिंताएं दूर होंगी और मैं एक बेहतर जीवन के बारे में सोच पाऊंगा। यह हमारे परिवार को आर्थिक तनाव से मुक्त होने में मदद करेगी।'' विजेता ने कहा।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रक: नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्रो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com